The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Hon. members must have by now heard of the large-scale armed attack made by regular Pakistan forces in the Chaamb sector. The attack which began yesterday morning by a brigade of infantry and 70 tanks was preceded by heavy shelling of our positions by the Pakistani artillery. The Pakistanis crossed the International Frontier close to the junction of the cease-fire line with the International Frontier. Because of the massive attack, Pakistanis have been able to make a salient of about five miles deep.

Yesterday evening our Air Force made a strike and in the combined resistance by our ground troops as well as the air strike, 13 Pakistani tanks were destroyed. Many enemy vehicles and guns were also hit. Two of our aircraft are missing and two have been damaged. Other casualties of the battle are not yet known.

The situation is under control; and necessary counter-measures have been initiated. Militarily it is a developing situation. The massive intervention of armour by Pakistan has escalated the conflict rapidly. We have to take an overall view of defence. Our troops are fighting bravely and confidently and I am certain that our forces are competent to meet any situation.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) *rose—*

Mr. Speaker: The desire is no questions might be put.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक आश्वासन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पटनायक साहब, कोई भी आश्वासन इस वक्त कौन दे सकता है । आश्वासन मांगने की बात कहना इस समय ठीक नहीं है ।

12.05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: Let us now proceed with further discussion of the Statutory Resolution moved by Shri Yashpal Singh and the motion moved by Shri M. C. Chagla "That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration".

Before we proceed with that, I have to make an announcement. The Minister will make a statement about Caravelle planes at 5.00 P.M. today.

Now, Shri Prakash Vir Shastri may continue his speech.

Shri Bade (Khargone): Sir, may I, in the beginning itself, request you to extend the time by one hour because yesterday even some of the leaders of the parties could not speak?

Mr. Speaker: All right, I will extend it by another hour. But now that should be the end.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में जो विधेयक शिक्षा मन्त्री की ओर से आया उसका समर्थन करते हुए और श्री यशपाल सिंह ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसका विरोध करते हुए मैं यह कह रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिस प्रकार भारत के और दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं । इस विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को बनाये रखने से यदि सरकार का यह अभिप्राय है कि मुस्लिम संस्कृति का भारतीय सम्प्रदाय निरपेक्ष नीति के साथ कैसे समन्वय हो सकता है इस बात को बनाये रखने के लिये वहां पर कोई व्यवस्था की जाये

और इसी का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को कायम रखना है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को बनाये रखने का अभिप्राय यह है कि वह पाकिस्तान का गढ़ बन जाये या कुछ राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले तो इस देश में इसे कभी सहन नहीं किया जा सकेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पिछले सत्रह सालों में भारत सरकार ने सहायता के रूप में जो पैसा दिया है वह 9 करोड़ 95 लाख 55 हजार 735 रु० के लगभग बैठता है। इस लगभग 10 करोड़ रु० में जो भारत सरकार के कोष से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दिया गया है, भारत के सभी निवासियों का पैसा है, जो सरकार टैक्स के रूप में उनसे वसूल करती है। हमारे संविधान की धारा 27 में यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि भारत के किसी भी निवासी को टैक्स देने के लिये विवश नहीं किया जायेगा यदि वह पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार और उसके संगठन पर व्यय किया जाये। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप केवल मुस्लिम रक्खा जाता है और उसके लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत में सुविधा रहती है तो भारत का संविधान इस 10 करोड़ रु० को देने की, जो कि भारत सरकार दे चुकी है, कभी इजाजत नहीं दे सकता था। इस दृष्टि से भी मेरा अपना अनुमान है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समझ कर ही भारत सरकार ने लगभग 10 करोड़ रु० दिया है।

मैं अब इस बात पर आता हूं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों हुई। चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पिछली परिस्थितियां इस बात के लिये विवश कर रही थीं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें। वहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति श्री अलीयावर जंग के साथ जो घटना अप्रैल मास में घटी वह भी इतनी दुखद थी कि उससे विवश होकर राष्ट्रपति को यह पग उठाना पड़ा। न केवल श्री अलीयावर जंग को पीटने के वास्ते यह षड्यन्त्र किया गया था बल्कि जैसी शिक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री को जानकारी होगी, जिस हाल में श्री अलीयावर जंग को लोग पीट रहे थे उसके बाहर उनको कब्रिस्तान तक ले जाने के लिये जनाजा भी तैयार था। उनको दफनाने तक का इन्तजाम कर लिया गया था। बल्कि श्री अलीयावर जंग को पीटते समय जो लोग उन को पीट रहे थे वह यह नारा लगा रहे थे कि "हैदराबादी मुर्गे, तू ने पहले तो हैदराबाद रियासत को खत्म किया और अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिये आया है।" इस नारे के पीछे उनकी मनोवृत्ति झलकती है कि किस मनोवृत्ति के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पीटा गया।

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की समिति वहां भेजी थी श्री नेकी राम शर्मा की अध्यक्षता में, और जिसमें मुसलमान और दूसरे सभी सम्प्रदायों के मेम्बर थे, उसकी रिपोर्ट का हवाला दूं। श्री नेकी राम शर्मा ने जो रिपोर्ट दी है वह भारत सरकार की आंख खोलने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये।

इसके साथ साथ मैं श्री नवल किशोर, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में शायद उपगृह मन्त्री थे उनकी रिपोर्ट की ओर भी आप का ध्यान खींचूंगा। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी तत्व पहले से मौजूद थे और श्री तैयब जी के समय में इस प्रकार की नियुक्तियां और हुईं जो पाकिस्तानी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मनोवृत्ति के लोग थे । यह सारी की सारी स्थिति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्दर बनी । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सन् 1947 के पहले क्या इतिहास रहा है, मैं उस दुःखद अध्याय को यहां पर नहीं छेड़ना चाहता कि किस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बैठ कर देश के विभाजन का षड्यन्त्र तैयार किया गया, किस तरह से मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रवादी लोगों का अपमान किया गया । वह बड़ी दुःखद बात होगी । अगर विस्तार से किसी व्यक्ति को पढ़ना हो तो डा० राजेन्द्र प्रसाद की पुस्तक "डिवाइडेड इंडिया" को पढ़ कर देख सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत की राजनीति में क्या रोल अदा किया है ।

मैं तो उन लोगों से जो यह कहते हैं कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई पाकिस्तानी तत्व नहीं हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई प्रतिक्रियावादी तत्व काम नहीं कर रहे हैं आठ दस प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

क्या वह लोग यह भूल गए कि के० एम० मुनशी की पुस्तक "रिलीजस लीडर्स" को लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हंगामा हुआ था ?

क्या वे लोग यह भूल गए कि जब डा० जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चासलर थे तो कुछ समय बाद उनको मजबूर होकर वाइस चांसलर के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था । उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं यहां बड़ी हसरत लेकर आया था, लेकिन बहुत नाउम्मीद होकर बीच में इस विश्वविद्यालय को छोड़ कर जा रहा हूं ।

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि यूनियन के चुनावों को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने साम्प्रदायिक फिजा को खराब करने के लिये क्या तरीके अपनाए थे ?

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि ओलम्पिक खेलों में जब पाकिस्तान की हाकी टीम जीती थी तो उस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया था और वाइस चांसलर को लिख कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय की छुट्टी रखी जाए ?

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चार पांच साल तक लगातार 14 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता रहा क्योंकि पाकिस्तान का जन्म उसी तारीख को हुआ था, और बाद में जब गृह मन्त्रालय को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसको बन्द करवाया ?

क्या उन लोगों को यह पता नहीं है कि जिन्ना के मरने पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मातम मनाया गया था ।

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि अयूब के दोबारा चुने जाने पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में किस तरह मिठाइयां बांटी गयीं ?

क्या उनको पता नहीं कि जमाते इस्लामी का पहला कनवेंशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी में हुआ और उसमें भारत सरकार और भारत के खिलाफ जहर उगला गया ।

क्या उन को पता नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो अपनी पुस्तक लिख कर माओत्से तुंग को भेंट करते हैं ।

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसे तत्व भी थे जो भारत का लाखों रुपया ले कर पाकिस्तान चले गए और भारत सरकार को वह रकम बट्टे खाते डालनी पड़ी ।

क्या इस के बाद भी हमारे दोस्त यह कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रतिक्रियावादी तत्व नहीं हैं ? मैं नहीं समझता कि ठाकुर यशपाल सिंह जैसे जिम्मेवार आदमी ने कैसे अपने भाषण में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोग नहीं हैं। ठाकुर यशपाल सिंह ने अपने भाषण में यह दावा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तान को डा० सैयद महमूद जैसा राष्ट्रवादी दिया। डा० सैयद महमूद को जो पिछले कुछ सालों की गतिविधियां हैं, मैं उन में नहीं जाना चाहता। अगर होम मिनिस्ट्री के पास मुस्लिम कनवेंशन की रिपोर्ट हो तो उस को पढ़ कर देख लें ? मैं तो एक ही चीज अपनी बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री श्री चागला इस बात का उत्तर दें कि क्या उन को डा० सैयद महमूद ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो आर्डिनेंस निकाला गया उस के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था कि यह जो आर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, इस का पाकिस्तान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि श्री चागला ने इस पत्र का क्या उत्तर दिया। पर मैं जानना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि क्या डा० सैयद महमूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हिन्दुस्तान में पाकिस्तान का भाग बना कर रखना चाहते हैं शायद इसी लिए वह कहते हैं कि इस आर्डिनेंस की पाकिस्तान पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान के लिये बना है या हिन्दुस्तान के लिए बना ? और इतना होने पर भी ठाकुर यशपाल सिंह डा० सयद महमूद पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि डा० सैयद महमूद जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पैदा किया है। मैं डा० सैयद महमूद की अन्य हरकतों में इस समय नहीं जाना चाहता।

लेकिन मैं आप से एक बात और कहना चाहता हूं। अभी आल इंडिया मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में इस आर्डिनेंस को ले कर एक कनवेंशन हुआ, जिस की अध्यक्षता डा० सैयद महमूद ने की और उन्होंने वहां पर जो जहर उगला उसे मैं आप के सामने रख सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है।

लेकिन मुझे इस से भी अधिक दुःख की एक बात प्रधान मंत्री जी से विशेष रूप से कहनी है। मेरी प्रार्थना है कि श्री सत्य नारायण सिंह जी दो मिनट के लिए अपनी बात बन्द कर दें जिस से मैं प्रधान मंत्री जी से अपनी बात कह सकूं। मैं ने सुना है जो प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री श्री चागला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यादेश को लेकर जिस बहादुरी के साथ पिछले दो महीने से सारे विरोध का मुकाबला कर रहे हैं, उस के लिए वह हम सब के बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी की आंखें खोलने के लिये उन से पूछना चाहता हूं कि क्या श्री चागला जो अकेले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में लड़ रहे हैं, उन के मंत्रिमंडल के दो सदस्य ऐसे हैं जो श्री चागला के खिलाफ किए गए इस अभियान में, जो उन को बदनाम करने के लिए हो रहा है, अन्य लोगों का साथ दे रहे हैं ? मैं इस को और भी खुले रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इस के कुछ प्रमाण भी हैं, मैं सप्रमाण इस चीज को कह रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाए मेरा इशारा श्री हुमायूं कबिर और जनरल श्री शाहनवाज खां की ओर है। यह जो जमीयत उल उलेमाए हिन्द, जिसने सब से बड़ा केम्पेन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस आर्डिनेन्स को ले कर चला रखा है...

श्री रामेश्वर व्यास (उज्जैन) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या है आप का प्वाइंट आफ आर्डर ?

श्री रघुनाथ व्यास : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अगर किसी को मिनिस्टर के खिलाफ एलीगेशन करने हों तो उस को उस का इंटीमेशन देना चाहिए। यह रूल्स में दिया हुआ है। माननीय सदस्य ने इस के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन की यह बात ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेना हो या उस की नुक्ता चीनी करनी हो तो उस का प्रीवियस इंटीमेशन देना जरूरी है। पर अगर वह किसी के स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं तो मैं उस को नहीं रोक सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में यह कहना चाहता हूं कि जमायते उल उलेमाय हिन्द, जिस ने श्री चागला के खिलाफ यह अभियान जारी किया हुआ है, उन की जो गवर्निंग बाडी है उस में केन्द्रीय मंत्री मंडल के दो सदस्यों को नामिनेट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में सारे मंत्रिमंडल की साझी जिम्मेदारी है। या अकेले श्री चागला की जिम्मेदारी है ? अगर सब की साझी जिम्मेदारी है तो उन्हें उस अभियान का विरोध करना चाहिए था जो जमैयत द्वारा श्री चागला के खिलाफ चलाया जा रहा है।

इसी सम्बन्ध में दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं जो चार संस्थाएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस को ले कर भारत सरकार और श्री चागला को बदनाम कर रही हैं। क्या मंत्रिमंडल के उन सदस्यों की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि इस के विरोध में बोलते और अपनी राय जाहिर करते। और अगर वह अपनी राय भी न जाहिर करते तो जमैयत उल उलेमाय हिन्द की गवर्निंग बाडी से तो त्यागपत्र दे सकते थे यह कह कर कि इस प्रकार के संगठन में वे नहीं रहना चाहते जो सरकार के और मंत्रिमंडल के एक सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान चला रही है। मैं किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चर्चा में नहीं जाना चाहता और मैं नहीं कहना चाहता कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक इस प्रकार का सदस्य है कि उस का समीप का रिश्तेदार पाकिस्तान में डाइरेक्टर जनरल आफ इन्फार्मेशन के पद पर काम कर रहा है।

मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन को मुसलमानों की एक संस्था यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के लीडर श्री असरारुलहक द्वारा, जो पहले मध्य प्रदेश की विधान सभा के एम०एल०ए० थे, कोई ज्ञापन भेजा गया है जिस में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि श्री चागला के खिलाफ जो कैम्पेन जारी है उस में वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च किया जा रहा है ? क्या उन को इस प्रकार का ज्ञापन मिला है ? और अगर आप को वह ज्ञापन मिला है तो उस में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह इस प्रकार की बातों में रुचि लेते हैं, लिहाजा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्री हुमायूं कबिर को हटा दिया जाए ? क्या यह बात सही है ....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप को उस की कापी भेजी गई है। आप बहुत सी बातें कैबिनेट के मैम्बरों के बाबत कह गए। मैं कहूंगा कि हर मैम्बर को पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। जिस वाकये का वह जिक्र करते हैं उस के बारे में पूरी जिम्मेदारी उन को लेनी चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और अगर मेरी बात गलत हो तो प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जो यहां बैठे हैं उस का खंडन कर सकते हैं।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Last time, Mr. Prakash Vir Shastri made many allegations on the floor of the House.

But when the Chatterjee Committee Report came, many of his charges were not substantiated.

अध्यक्ष महोदय : यह बात मेम्बर के लिए कहना काफी नहीं है । जो वह कहते हैं उस की जिम्मेदारी उन को लेनी चाहिए । अगर कोई किसी के खिलाफ एलीगेशन लगा दे और फिर वह कहे कि अगर यह गलत है तो इस की तरदीद कर दी जाय, तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो उस एलीगेशन से किसी का नुकसान हो सकता था वह तो हो गया, एक आदमी बदनाम हो गया । उस के खिलाफ एक आवाज पैदा हो जाती है । बाद को अगर वह गलत भी साबित हो जाए तो भी जितना नुकसान होना था वह हो चुकता है । तो यह कहना काफी नहीं है कि अगर यह बात गलत है तो इस की तरदीद कर दी जाए । मेम्बर को जो वह कहें उसके बारे में अपनी पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वह बात सही है, और उस पर यकीन करने के लिये उन के पास काफी वजूहात है । जब तक ऐसा न हो तब तक उन को स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस तरह का नाम ले कर हमला किया है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : यह हमला नहीं है । इस में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है । मेरा श्री हुमायूं कबिर से बात हुई थी, वह जमैयत उल उलेमाए हिन्द के सदस्य नहीं हैं । तो एक बात तो यही गलत निकलती है ।

दूसरी बात उन्हों ने यह कही कि उन्हों ने इस का विरोध नहीं किया, इस की मुखालिफत नहीं की, कहीं कोई स्पीच नहीं की, किसी ग्रुप में डिस्कशन नहीं किया पब्लिक में किसी शक्ल में इस का विरोध नहीं किया । यों तो किसी भी कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स की एक राय हो सकती है, या दूसरी हो सकती है । लेकिन जो फैसला होता है कैबिनेट का वह आखिरी होता है और वह सब के लिए मान्य है । तो मैं यह समझता हूं कि जिस तरह का आक्षेप या हमला उन्हों ने किया है, यह न करना चाहिए था । मुनासिब तो यह होता कि वह ये चीजें लिख कर हम को भेज देते और हम उस का जवाब उन को देते । तब भी अगर वह यह समझते कि नहीं उन के पास कोई सबूत है और बातें हैं, तो उन को वे बातें यहां कहने का हक था । लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का उन्हों ने आक्षेप किया है यह ठीक नहीं था और न उस में सचाई है उस तरह की जो उन्हों ने कहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात आप से कह रहा हूं मैं बिना किसी प्रमाण के कहने के लिए तैयार नहीं था । मैं ने तो पहले मंत्रिमंडल के केवल दो सदस्य कहे लेकिन जब उधर से आवाज आई कि उन के नाम बता है तो मुझे विवश हो कर उन दोनों के नाम भी लेने पड़े । वैसे मैं उन के नाम यहां पर लेने को तैयार नहीं था । प्रधान मंत्री जी ने जो अभी यह बात कही कि वह गवर्निंग बाडी के मैम्बर नहीं हैं तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधान मंत्री की जानकारी किस आधार पर है लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है अलजमीयत जो कि उन का प्रमुख अखबार है उस के 21 जुलाई के अंक में यह समाचार छपा है कि जमीयत के जो प्रेसीडेंट हैं मौलाना फखरुद्दीन उन्हों ने गवर्निंग बाडी में जिन लोगों को नामिनेट किया है उस में इन दोनों व्यक्तियों के नाम हैं । क्या प्रधान मंत्री जी यह कह सकेंगे कि इस समाचार की जानकारी लेने के बाद उन्हों ने कोई त्यागपत्र दे दिया है या नामिनेट होने के बाद उस से अपनी असहमति प्रकट की है ?

दूसरी सब से बड़ी बात जो आप ने मुझ से पूछी है वह यह है कि यह जो रिप्रेजेंटेशन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

प्रधान मंत्री को दिया गया है, मैं शायद इस बात को अधिकारपूर्वक नहीं कहता । यदि मेरे पास उस की प्रतिलिपि न होती और उस में यह बातें न होती लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बात के लिए तत्पर हूं कि उन को हाउस की टेबुल पर भी रख दिया जाय जो कि इन लोगों की ओर से यह रिप्रेजेंटेशन प्रधान मंत्री जी और दूसरों के नाम आया है ताकि उस की जानकारी केवल गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को ही न हो बल्कि संसद के सारे सदस्यों को भी हो जाए । इतने पर भी मैं कहता हूं कि मैं उस में खुश हूंगा अगर मेरी इस सम्बन्ध की जो जानकारी है वह गलत निकले और उस के अन्दर कोई उच्चाई न हो । राष्ट्र का भला भी इसी में है । लेकिन अगर उस में कुछ भी सच्चाई है तो मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि अकेले श्री चागला को ही बलि का बकरा न बनाया जाय । प्रधान मंत्री के ऊपर भी तो इस का लाछन आता है क्योंकि इसी मंत्रिमंडल में वे लोग बैठते हैं । एक ओर श्री चागला इस प्रकार की आज्ञा जारी करते हैं तो दूसरी ओर उन के सहयोगी एक बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज करते हैं ।

मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और कहना चाहता हूं

श्री लाल बहादुर शास्त्री: अब यह कहना कि अखबार की यह बात है तो अखबार में बहुत सी बातें निकलती हैं और वे सब कोई सोलहों आने सही नहीं हुआ करतीं । जहां तक श्री हुमायूं कबिर की गवर्निंग बाडी में होने की बात है अब चूंकि उन्हों ने फिर दुहराया है तो मैं उन को बतला देना चाहता हूं कि मैं ने उन से खुद बातचीत की, वह कभी उस के मेम्बर नहीं रहे तब यह इस्तीफे का सवाल ही क्यों पैदा होता है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रधान मंत्री शास्त्रीजी से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चीज अखबार में प्रकाशित हो जाती और श्री हुमायूं कबिर अपना अब तक एक वक्तव्य दे सकते थे कि मैं उस में नहीं हूं मैं गवर्निंग बाडी का मेम्बर नहीं हूं ।

Shri H. C. Mathur (Jalore): Mr. Speaker, Sir, I submit for the information of the hon. Member that Mr. Chagla does not stand alone in this matter. We had an Executive Committee meeting and in that meeting Mr. Chagla was told that each and every member of the Congress Party was behind him and was with him. Therefore, it is with the entire support of the Congress that Mr. Chagla is going ahead. The Executive Committee, in its meeting, gave Mr. Chagla a clear understanding that they all were behind him.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य हैं उन्हों ने श्री चागला के इस पग के लिए माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें समर्थन दिया । अगर मैं सब सदस्यों की चर्चा करता तो श्री माथुर का वक्तव्य उचित होता लेकिन मैं तो चर्चा कर रहा था कैबिनेट के सदस्यों की जिन की ओर से इस प्रकार की चीजें चली हैं ।

मैं एक, दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा । एक तो यह कि जो लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो सकती तो उन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि 1920 का ऐक्ट इसी हाउस ने पास किया था । इसलिये 1951 में इस हाउस को अधिकार हुआ कि उस में परिवर्तन करे और जब उस समय उस को अधिकार था तो आज भी अपने उस ऐक्ट में उसे परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है । जो लोग यह कहते हैं कि उस में अंगुली नहीं लगा सकते वे शायद संविधान की इन व्यवस्थाओं से ही अपरिचित हैं ।

दूसरी चीज यह कि जब यह विश्वविद्यालय मुस्लिम कालिज था उस वक्त भी इस विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट की ग्रान्ट्स मिलती थीं इसलिए इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कहना कि केवल यह मुसलमानों की ही प्रोपरटी है सारे राष्ट्र का उस में कुछ भाग नहीं है वह उस समय के इतिहास से अपरिचित होना है ।

अन्त में मैं यह कहता हूं कि श्री चागला ने इस विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वरूप को कायम रखने के लिए जो यह विधेयक उपस्थित किया है मैं उस का समर्थन करता हूं और ठाकुर यशपाल सिंह के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

Mr. Speaker: Now, Shri Mohsin. The hon. Member is not here. Shri Swell.

Shri Swell (Assam—Autonomous Districts): I wish that a discussion on the affairs of a high seat of learning such as a university, and in this case, the Aligarh Muslim University, should have started on a higher, a more objective and a more intellectual note. I wish that my hon. friends in this House who participated in this debate had brought their reason more than their emotions to bear on the subject so that we could have judged the merits and demerits of this Bill in a better way.

My hon. friend Shri Yashpal Singh when he initiated this discussion the other day started on a very high-strung and a very emotional note, and I got the impression that he was trying to outdo even such communal members, if there be any, among the Muslim minority community, in his denunciation of the Hindus. It was altogether irrelevant to the subject under discussion before us.

The ball which Shri Yashpal Singh threw at the court of the ruling party, namely the Congress Party, was firmly grasped by my hon. friend Shri Raghunath Singh. I was surprised to hear from him, a senior Member of the Congress Party, a very strange and an elaborate attempt to put a wrong interpretation on article 28 of the Constitution in order to do away with certain safeguards and certain fundamental rights given to the minorities, which the Constitution had so plainly conferred on them. And just now, we have had the good fortune or the misfortune of hearing a very indignant speech from my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri, in which very serious and sweeping charges have been made not only against certain members of the Muslim community but even against certain prominent Members of the Cabinet. May I submit to you and through you to this House that it is these kinds of speeches from the Members of the majority community that go to lend an air of legitimacy to the fears of the Muslim minority community with regard to the effects of this Bill?

I do not also agree with much of what my hon. friend Shri Badrudduja said yesterday. I understand and appreciate his passionate plea for the cause of the minorities, particularly the Muslim minority. But when he went to the extent of making a sweeping charge against the Minister of Education, Shri M. C. Chagla, that Shri M. C. Chagla wanted to throttle Muslim culture, I think he was less than fair to the Education Minister. I also do not agree with the approach of another Member of the Congress Party yesterday who vomitted the tea and the sweet that was served to him by the late Shri Rafi Ahmed Kidwai, that there is only one culture in India and that is the Indian culture. This is a vague and dangerous talk. It is the kind of talk that is not intended to clear the atmosphere; it is the kind of talk that will go to reinforce the fears of the minority communities that the majority community wants to overshadow the culture of the minorities with its own culture or impose its culture on that of the minorities. Ours is a variegated nation. We talk of unity in diversity. Whether we like it or not, history tells us that this is a country

[Shri Swell]

inhabited by people belonging to different cultures, to different faiths, to different traditions and to different racial stocks.

It is true that there can be such a thing as an Indian national culture, an Indian personality, but that culture can only be an amalgam of the different cultures we have in this country, and if that culture is to be a culture of a high order that would merit the respect of the world, it must come out of the growth and careful and loving nurture of the different stands of culture we have in this country.

In spite of what my hon. friend, Shri Mathur, has said that the party has decided to give Shri Chagla unqualified support to this Bill, I am afraid that he has been badly let down or badly supported by the spokesmen of his party. I feel that it was Shri Chagla himself who could have put his case more effectively. There cannot be a second opinion to what Shri Chagla holds that what happened in the campus of Aligarh Muslim University on 25th April last was heinous in the extreme, that it demanded immediate drastic action. I think on that score, he has received the entire support of every section of this House.

An hon. Member: Not every.

Shri Swell: But the question remains—and it has not been satisfactorily answered by the Education Minister—whether the law of the land in its ordinary course could not have been employed, whether the law of the land could not have met the situation, whether it could not have stamped out the evil, whether it was necessary at all to resort to the ordinance, and now to this Bill, in order to effect certain administrative changes in the structure of the University.

May I submit that this country of late has been subjected periodically to outbreaks of student indiscipline? May I quote a few instances for your information? In the month of June this year, the students of the Gauhati University in Assam surrounded the office of the Vice-Chancellor, imprisoned him there for hours together, damaged his office and threatened to do away with him physically, because they wanted changes in the dates of the M.A. final examination; and the Vice-Chancellor could save himself from possible death only by fleeing the town of Gauhati.

Prior to this, as you know, the students of Orissa invaded the precincts of the Orissa Legislative Assembly and demanded the resignation of the Chief Minister of that State. Here in the case of Aligarh University, we have been told that the students were worked up because of the raising in the percentage of students from outside to be admitted to the University, we would like to be satisfied how this is a pre-planned, pre-conserted, attempt to murder the Vice-Chancellor, as the Education Minister has said, because the Vice-Chancellor has liberal and nationalist views. We would like to be satisfied how this is the work of reactionary and obscurantist elements in the university, and that this is not only one of those violent and extreme outbreaks of student indiscipline. I think the Minister of Education should have taken us more into his confidence. He should have explained that point clearly to us, leaving no amount of doubt, that this is really a case of a pre-planned attack by certain reactionary and obscurantist elements, as he puts it. The doubt lingers whether the Ministry of Education has correctly diagnosed the cause of the disease, whether the Bill which he now brings before the House will really be a cure for the malady that has afflicted that university, whether this remedy may not prove worse than the disease.

I for one am prepared to take the Minister of Education at his word. I

am not prepared to discount everything that he has said. His background, his standing, his standing in society, his long record of public service, his high position in the Cabinet and his general disposition would persuade me to believe in what he says, but still I feel that it is his duty to convince me. We are not here a gullible lot; if we were a gullible lot, we have no right to be Members of this responsible House. We would like to be convinced by reason and not just by a statement by the Minister, however highly placed he may be.

The Minister, in making out his case, has based it on two pillars. One is that this Bill is a temporary emergency measure, that it will not remain on the statute-book, that as soon as may be, perhaps in the next session of Parliament, he will bring a substantive Bill to amend the original Act of this university. The second is that the Bill is not going to affect the character of the university, its courses of study, that the Academic Council will remain in tact, that the culture, the traditions and the philosophy of Islam would remain intact. I wish the Minister, in seeking a fulfilment of these objectives, had put more thought in the drafting of the Bill. As it is, I do not agree that this Bill will remove the fears and the doubts, the genuine doubts and fears, of the minority Community. May I draw your attention to the provisions in the original Act in which the provision is made for representation of certain important sections in the court of the University: donors of the university, the All India Muslim Educational Conference and persons representing Muslim culture and learning. The Minister has said that the Court will be a nominated court. What prevents him from making this addition in the relevant provision of his Bill to ensure that in making these nominations, the nominations will be made from these three groups of people, the donors to the university, the All India Muslim Educational Conference and persons representing Muslim culture and learning. Let us not forget the fact that the Aligarh Muslim University was built up by the sacrifices, endeavours, earnings, hopes and fears of generations of Muslims from 1867 to 1920. They did this because they wanted that the Muslim culture, Muslim philosophy and Muslim religion should have a chance of developing alongside with the development of modern arts and sciences. What the Government of India did in 1920 and in 1951 was only to give legal sanction to what the Muslim genius and Muslim endeavours had built up in the past. It is for these reasons that some of us felt that the matter be best referred to a Select Committee in which we would have a free, personal and closer exchange of views with the Minister and we can have the benefit of his reaction. Sir, I understand the difficulty of the Minister of Education. He has a time limit of six weeks. But may I submit to him that well before that time limit is over, the Select Committee would be able to send its report. But if he still thinks that the Select Committee is not necessary, to remove the genuine doubts and fears, I earnestly suggest to him that he may consider even now the incorporation of at least this part in the Bill which he has placed before the House.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Speaker, it is unfortunate that the Aligarh Muslim University Ordinance raised certain apprehensions in the minds of Muslims of the country. I submit that these are not justified. The ordinance of 20th May was resorted to, because Parliament was not sitting and immediate measures were necessary to bring about normalcy in the University. The atmosphere there was vitiated by fanaticism and obscurantism both among the students and the teachers of the University and certain unhealthy elements were attempting to get the upper hand in the University and so the Ordinance was promulgated on 20th May, 1965. Eminent Indian Muslims including the

[Shri Muthiah]

Members of Parliament and educationists deplored the Aligarh incidents, and prominent papers of the country have condemned the reactionary elements in the University. Official sources believe that the disturbances have their roots in the constitution of the University which tended to encourage a vicious atmosphere, not conducive to the healthy functioning of the university.

This Ordinance has a precedent in the Banaras Hindu University Ordinance of 1958. In 1958 disturbances broke out in Banaras. Whereas in Banaras, the Vice-Chancellor was locked up in a room, in Aligarh, in April, 1965 the students mounted a murderous attack on the Vice-Chancellor, Nawab Ali Yawar Jang who received serious injuries and only providentially escaped from fatal consequences. Following the example of the Banaras Hindu University Ordinance, the Aligarh Muslim University Ordinance sought to suspend the constitution of the Aligarh University Act for the time being and to reconstitute the Court and the executive council on the basis of nomination for a temporary period. In the 1920s, sometime after the Aligarh University was established, a similar situation arose and a similar measure was taken. A knowledge of the history of the Aligarh University would be useful to understand the implications of the Ordinance and the Bill. The idea of establishing a Muslim University at Aligarh was first conceived by that great son of India, Sir Syed Ahmed Khan in 1867. He wanted to rehabilitate the Indian Muslims frustrated by the failure of the 1857 freedom movement by providing for them modern and scientific education in an atmosphere of Islamic culture and traditions. Thanks to his efforts, the Aligarh University came into being in 1920 with the passing of the Act in 1920. The amending Act of 1951 made some changes in the constitution of the university court and in respect of learning of Muslim theology by students. In 1959, at the instance of the Central Government, an enquiry committee under the chairmanship of Prof. Chatterjee was set up by the Aligarh University and this committee submitted its report in 1961. The report made it clear that the aim of the university was to preserve the best thought and culture of the Muslims while providing higher education to its students. The report further said that the amending Act of 1951 did not alter its fundamental character as a Muslim University intended for the educational advancement of the Muslim youth.

I come to the admission policy of the University. From the very beginning, the university has followed a policy of throwing its doors open to non-Muslims. While giving preference to the Muslims, the University has always admitted non-Muslim students. The non-Muslim students of the Aligarh University today are 35 per cent. So it is not a question of Muslim students versus Hindu students, but it is a question of the local students of Aligarh who wish to preserve their vested interests versus the students of the rest of India.

I will now refer to the admission rules of the University. The immediate cause of the riots was, ostensibly, the decision of the admission committee of the University to revise the ratio of internal students to external students as 50:50 instead of 75:25. For a long time the ratio was 50:50. Only recently, the previous Vice-Chancellor Mr. Tyabji raised the ratio of internal students to external students to 75:25. The enquiry committee set up by the University in 1959 recommended the ratio of 50:50 for internal and external students for admission to the college of Engineering. The purpose of the new measure, i.e., the revision of the

ratio of admission according to the present Vice-Chancellor's explanation was to give opportunities to far better qualified Muslim students from outside Aligarh and thereby ensure higher standards. This would help in main aining the All India character of the University. He reiterated this view in his speech at Aligarh on 29th August, 1965. This change in the admission rules was exploited by certain undesirable elements among the students and teachers to instigate a revolt and violence in the campus. They gave it a communal twist and used it against the Vice-Chancellor, well-known for his national and secular outlook.

The Ordinance and the Bill provide for certain organisational and structural changes in the constitution of the University. The basic character or the original purpose of the university is not affected or altered.

The University was first started (1) to promote the education of the Muslim youth, (2) to promote the study of Islamic history and culture and Islam's contribution to the composite culture of India and to the world's culture, (3) to teach Islamic philosophy and theology to Muslim students, and (4) to teach Arabic, Persian and Urdu literatures. These aims and objects are not interfered with by the Ordinance or the Bill. Research on Islamic history and culture is still carried on by the University. Thus everything is being done to foster the best in Muslim thought and culture, but Muslim fanaticism or exclusiveness is not encouraged in the campus and can never be encouraged. The Government of India stands for secularism, communal harmony and national unity and integration. India is a land of different castes and creeds, communities and cultures. As such, national unity is its paramount need. The Government cannot afford to allow the Aligarh Muslim University or any other university to function in a narrow and commnal way. The Aligarh students should be infused with a truly national spirit.

The Aligarh Muslim University is a unitary and residential university and it is in such universities that students of all creeds, the Muslims, the Hindus and the Sikhs, should learn to live together and imbibe that tolerance, so essential for India's peace and progress.

A university is a temple of learning and its precincts therefore are sacred. In such a place, there should be no room for hatred or illwill against anybody, and creed, any culture or any community. The Muslims and the Hindus should live together as brothers and as sons of the same soil.

Sir, I now come to the Bill. The present Bill is a temporary measure. The hon. Minister of Education has assured us that he is going to introduce a comprehensive Bill for the Aligarh Muslim University on the model of the Banaras Hindu University Bill which has already been introduced in Parliament. This Bill introduces a few structural changes. The membership of the court is to be reduced. The members, other than *ex-officio* members, will be nominated by the Visitor. Previously they were elected. But this nomination is a temporary measure necessitated by the recent, turbulent conditions in the Aligarh Muslim University. The court is to function as a purely advisory body for the Visitor. The membership of the executive council also is to be reduced. New statutes and ordinances pertaining to the administration of the university have to get the previous approval of the Visitor. Certain special powers are vested in the Vice-Chancellor and the Registrar in the matter of discipline. These steps are taken to tide over the present difficulties.

The Aligarh Muslim University, like any other university, should stand for national unity. It should not violate the fundamental principles of a secular State. Secularism is a precious heritage that we have inherited. Our constitution has declared India

[Shri Muthal]

as a secular State. Secularism, according to our Constitution, means equal regard for all religions and not disregard of religion or religious values. India lives if secularism lives: India falls if secularism falls.

I plead in the best interests of my country that the staff and students of the Aligarh Muslim University should live as true Indians, while revering their religion and culture, and pray that the university should produce eminent patriots in the future, as it produced in the past such great patriots as Khan Abdul Ghaffar Khan, Dr. Ansari, Dr. Zakir Hussain and Mr. Kidwai.

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद) : जनाब स्पीकर साहब, मुझे आज इन्तहाई अफसोस के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी पर गलत नाफिज होने वाले आर्डिनेन्स के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना है।

मुस्लिम अलीगढ़ यूनीवरसिटी में 25 अप्रैल का एक मामूली सा वाकया और उस पर हुकूमत का गैर मामूली रद्दे अमल और जारहाना इकदाम और मिस्टर चागला की जिद व जवां दराजी ने एक ऐसा फितना खड़ा कर दिया कि अगर उस को तदबीर और दूरन्देशी के साथ हल न किया गया तो हमारी मुश्तरका कौमियत और सिक्यूलरिज्म की बुनियादें तबाह हो जाएंगी, और हुकूमत जो मुल्क के आईन की मुहाफिज और उसके मकासिद की तकमील व तामील की जिम्मेदार है, उस पर आईन के मंशा से इनहराफ का इल्जाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा।

नवाब अली यावर जंग की शान में गुस्ताखी के वाकया को हजारहा हाशिया आराइयों के साथ उछाला जा रहा है, वह काबिले अफसोस है, इसलिए कि मजलिसे कानून साज के बयान के मुताबिक कुल मजमा 600 तुलवा पर मुश्तमिल था, और यूनियन हाल पर धावा बोलने वालों की तादाद का अन्दाजा इससे कीजिए कि हाल और उस के बरामदों में पचास साठ तुलवा की गुंजाइश है। उनमें वह भी थे जो बचाने वाले थे। गोया इस तजजिया की रोशनी में यूनीवरसिटी के साढ़े पांच हजार तुलवा में उन शरारत पसन्दों का तनासुब जिनके खिलाफ यह कारंवाई हो रही है, दाल में नमक के बराबर भी नहीं पहुंचता। उनको आप चागला साहब की जबान में रजअत पसन्द कह लें या फिरका परस्त कह लें। इन उंगलियों पर गिने जाने वाले तुलबा की सजा साढ़े पांच हजार तुलबा और 6 करोड़ मुसलमानों को दी जा रही है, जिन का मुस्लिम यूनीवरसिटी वाहिद तालीमी व सकाफी मरकज है। एक चूहे को मारने के लिए मिस्टर चागला ने जो तोप दागी है, उन्हें यह तोप दागते वक्त देखना चाहिए था कि इसका गोला मुस्लिम यूनीवरसिटी के सीने पर पड़ रहा है या सिक्यूलर स्टेट की पेशानी पर पड़ रहा है।

यह इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम यूनीवरसिटी के मामूली से वाकये पर जो कुछ किया या करना चाहते हैं वह हर आम और खास और जिम्मेदाराने हुकूमत को मालूम है। बल्कि अगर मैं यह कहूं तो कोई गलत बात न होगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह 5 मई सन् 1965 के राज्य सभा के बयान के मुताबिक मरकजी हुकूमत के ईमा पर ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मिस्टर चागला को मुस्लिम यूनीवरसिटी की आंख का तिनका तो नजर आ गया लेकिन उन्हें दूसरी यूनीवरसिटियों की आंख का लट्ठा नजर नहीं आया। इससे मेरी मुराद यह है कि अलीगढ़ के मामूली से हादसे को इतना उछाला गया कि अन्दरून मुल्क से लेकर बेरून मुमालिक तक एक शोर मच गया और मालूम हुआ कि तुलबाए अलीगढ़ ने कितना बड़ा जुल्म ढा दिया। लेकिन पटना यूनीवरसिटी, गोहाटी यूनीवरसिटी लखनऊ यूनीवरसिटी, गोरखपुर यूनीवरसिटी, बनारस यूनीवरसिटी, उस्मानिया यूनीवरसिटी, उड़ीसा यूनीवरसिटी,

हर जगह ऐसे और इससे बदतर वाकयात हो चुके हैं जिन में अफसरान के साथ नाजेबा सुलूक किया गया, जूते फेंक कर मारे गए, कमरे में बन्द रखा गया, मोटरों में आग लगा दी गयी, खुद लखनऊ यूनीवरसिटी के तुलबा की तहरीक में वाइस चांसलर और गवरनर दोनों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन कभी ऐसे और इतने संगीन इल्जामात न आयद किए गए, न वहां के इन्तिजामी अमूर में कोई दखल दिया गया ।

जुनूबी हिन्द के तुलवा के हंगामे, हिन्दी दुश्मन तहरीक से तमाम तहरीकें तशद्दुद की इस मंजिल तक पहुंच गई जहां कि रियासती पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम रही और मजबूरन फोर्स तलब करनी पड़ी ।

लेकिन इसके बावजूद वहां मुल्क की सालमियत और तालीमी अदारों के वकार को न कोई खतरा नजर आया और न वहां किसी आर्डिनेन्स की जरूरत महसूस हुई । न तालीमी अदारों के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई तबदीली की गयी । न वहां कोई पाकिस्तानी एजेंट नजर आया, न वहां कोई रजअत पसन्द व फिरका परस्त दिखाई पड़ा और न वहां की जड़ें कहीं और दिखाई पड़ीं । लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी के तुलबा का अपने हकूक के तहफ्फुज करने के लिए एक मामूली सा मुजाहिरा जिसे फिरकावारियत से कोई ताल्लुक न था और जिसे महज वाइस चांसलर की नाआकबत अन्देशी, पुलिस की तुलबी और तुलबा पर बिला जरूरत फायरिंग ने एक मुश्तैल हुजूम की सूरत दे दी । जिसके नतीजे में तुलबा ने बेकाबू हो कर वाइस चांसलर को मारा । यह फेल इतना खतरनाक तसव्वर कर लिया गया कि जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत को मुरव्वजा कानून के अम्बार और इन्तिजाम को बेबस पा कर एक गैर मामूली आरडिनेन्स से मुसल्लह होना पड़ा ।

मुझे इन्तहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि . . .

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वह अपनी स्पीच को पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच को पढ़ रहे हैं । मैं इस बार में आप से कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पा रहा क्योंकि आप ने एक बार भी मेरी तरफ़ नहीं देखा । अगर आप एक बार भी मेरी तरफ देख लेते तो मैं कह सकता था कि आप नहीं पढ़ रहे हैं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन मैंने इसलिए आपकी तरफ़ नहीं देखा कि आप आर्डर, आर्डर न कह दें ।

मुझे इन्तहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि यह सब महज इसलिए हुआ कि एक अरसा से चागला साहब को मुस्लिम यूनीवरसिटी अलीगढ़ में फिरकापरस्ती का भूत नजर आ रहा था । उन्हें वहां के तुलबा की असरियत पाकिस्तानी एजेंट नजर आ रही थी । उनके तसव्वर की आंखों ने वहां के मैडीकल कालिज के निकले हुए तुलबा डाक्टरों को जिनके निकलने में अभी एक अरसा बाकी है ज्यादा तादाद में पाकिस्तान जाते हुए देख लिया । उन्हें अलीगढ़ में एक ऐसा कितनाही गिरोह नजर आया जिसकी जड़ें कहीं और हैं और मजबूरन मुल्क के तहफ्फुज व सालमियत के पेश नजर उन्हें आर्डिनेन्स के नफाज की सिफारिश करनी पड़ी । समझ में नहीं आता कि आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, जनाब हुमायूं कबीर वगैरह जैसे साहिबुल नजर लोग बजोर तालीम रह चुके हैं । मगर उनकी आंखों ने कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवरसिटी में न इन बुराइयों को देखा और न उनकी वजारत को यूनीवरसिटी के इन्तिजामिया में इस किस्म की मदाखलत की जरूरत महसूस हुई, जब कि उनकी कौम परस्ती मशहूर है । जाहिर है कि यूनीवरसिटी में अगर कोई ऐसी खामी होती तो वह उसे हरगिज नजरअन्दाज न करते । लेकिन चागला साहब की तोजैदा कौम परस्ती ने वह सब कुछ देख लिया जिसकी

[श्री मुजफ्फर हुसैन]

न कोई असल है न कोई बुनियाद उनके दिल और दिमाग में अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के बारे में एक स्कीम थी। जिस पर वह अमल करना चाहते थे। और इस अली यावर जंग के वाकए ने उनको इसका मौका अता फरमा दिया।

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि मिस्टर प्रकाशवीर शास्त्री ने ठाकुर यशपाल सिंह साहब के खिलाफ इस आर्डिनेन्स की मुखालिफत करने का इल्जाम लगाया है। मिस्टर यशपाल सिंह एक हिन्दू हैं और पक्के हिन्दू हैं, और इस हैसियत से उन्होंने इस आर्डिनेन्स की मुखालिफत की है। मैं प्रकाशवीर शास्त्री से कहना चाहता हूं कि जिस तरह वह मुसलमानों के खिलाफ मिस्टर चागला और अली यावर जंग को इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरह मैं भी मिस्टर यशपाल सिंह को बचाव में इस्तेमाल कर सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय : क्या आप ने श्री यशपाल सिंह से पूछ लिया है कि वह इस्तेमाल हो रहे हैं ?

13 hrs.

श्री मुजफ्फर हुसैन : इस में पूछने की क्या बात है ? उन्होंने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया था। दरअसल बात यह है कि वह एक इंसाफ पसन्द हिन्दू हैं, जम्हूरियत में यकीन रखते हैं और वह इंसाफ की बात कहना व करना चाहते हैं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने श्री यशपाल सिंह के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। ठाकुर साहब ने तो इंसाफ से काम लिया और इंसाफ के तकाजे के मुताबिक उन्होंने हमारी ताईद की है।

मि० चागला जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। अब यह कहना कि मि० अली यावर जंग के साथ जो कुछ हुआ अगर हम आर्डिनेन्स जारी न करते तो वाकयात उससे ज्यादा बदतर हो जाते, आग भड़क जाने की बात तबक्को थी और हालात उससे ज्यादा बदतर हो जाते, यह चीज सुन कर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि उड़ीसा के जंगलात में एक जानवर होता है जो कि मच्छर से कुछ ज्यादा बड़ा होता है और जब रात को वह आराम करता है तो वह अपने पैरों को ऊपर उठा कर आराम करता है। इस के लिए जंगल के तमाम जानवरों ने एक जलसा किया और उसमें उस जानवर से यह पूछा कि भाई और हम सब जानवर तो अपने सारे पैर समेट कर बैठते हैं और रात को अपने-अपने आशियानों में आराम करते है लेकिन तुम रात को अपनी टांगों को उठा कर आराम करते हो तो ऐसा तुम क्यों करते हो ? इस पर उस जानवर ने जवाब दिया कि तुम सब लोग बेवकूफ हो। मैं अपनी टांगें इसलिए उठा कर सोता हूं कि ऐसा न हो कि रात को आसमान गिर पड़े और तुम सब लोग उसके नीचे दब कर मर जाओ इसलिए मैं अपनी टांगों को ऊपर उठाये रहता हूं। अब जरा गौर कीजिये कि नन्ही सी टांगों के ऊपर आसमान को रोकने का हौसला ? श्री चागला का यह आर्डिनेन्स भी उसी जानवर की टांगों ऊपर उठाये रखने की दलील की तरह से है। यह आर्डिनेन्स मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तबाह करने का फैसला है। यहां मैं यह चीज साफ कर दूं कि मैं यह नहीं कहता कि उस में हिन्दू न पढ़ें सिक्ख व ईसाई न पढ़ें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर एक को चाहे वह किसी जाति का हो पढ़ने का हक हासिल है। हर शख्स उस मे दाखिला ले सकता है। हर शख्स को इस जम्हूरी हुकूमत में इस जम्हूरी दौर में उस में दाखिला लेने के लिए कोई बंदिश या रुकावट नहीं है लेकिन मि० चागला और अली यावर जंग की एक सोची समझी स्कीम के तहत जो कुछ किया जा रहा है उस के लिए हम आप से

जरूर इंसाफ के तालिब हैं और उस के मुताल्लिक मैं यह जरूर कहूंगा कि उस पर आप ठंडे दिल से गौर करें वरना मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और यह मैं दुखी दिल से अर्ज करना चाहता हूं कि ख्वाह वह प्राइम मिनिस्टर हों, ख्वाह उन की पूरी कार्बीना हो, अगर यह आर्डिनेंस जो मि० चागला ने अली यावर जंग की राय से जारी किया है तो क्या सन् 1967 के एलेक्शन में इसी का सहारा लेकर वे मुस्लिम कौम से वोट की भीख मांगेंगे ? साढ़े 6 करोड़ मुसलमानों के वोटों से आप यहां आये हैं और यह आप की तहरीरें हैं, यह आप की जबाबदेही है यह आप की तक़रीरें सब मैदान में हमारे सामने होंगी हम अवाम में उस बारे बतलायेंगे उस वक्त आप को मालूम होगा कि अवाम पर उनका क्या असर पड़ा है ? उस वक्त आप से पूछा जायगा कि आर्डिनेंस की मुआफिकत का क्या नतीजा होता है ? हमारी 62 युनिवरसिटियों में यह एक मुस्लिम इदारा है जिसके कि साथ आप यह बेइंसाफी फरमा रहे हैं। आप हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं वह आपके सामने मौजूद है इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इंसाफ से काम लेते हुए यह आर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया है उस के वापिस लेने पर आप उन्हें मजबूर करेंगे। एक सैकुलर स्टेट के अन्दर एक जम्हूरी हुकूमत के अन्दर यह समारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मान लो कि चन्द तुल्बा ने कोई ऐसी हरकत की जिसकी कि वजह से यह आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत महसूस हुई तो आप बजाए यह आर्डिनेंस इश्यू करने के क़तई तौर पर उन बच्चों के खिलाफ अदालत में मुकदमात चला सकते थे और वे बच्चे मुजरिम हैं या नहीं इसका फैसला अदालत पर छोड़ देते लेकिन एक माहिरे कानून होते हुए वक्त से पहले आप ने जो मुख्तलिफ़ बयानात उन बच्चों के खिलाफ या अलीगढ़ के खिलाफ़ दिये हैं हो सकता है कि इसका असर उनके मुकदमात पर पड़े। आप एक जज रह चुके हैं। आपके सामने कानून की हर दफात मौजूद हैं। आपके बयानात से उनके मुकदमात मुतासिर हो सकते हैं। आपने बयान दिया है कि बच्चों पर वहां मुकदमात नहीं चल रहे हैं लेकिन अभी 26 तारीख को एक 107/117 का मुकदमा था। इसके अलावा अभी दो रोज का वाकया है पांच बच्चे जिनकी कि जमानतें ली गई थीं लेकिन उस के बाद भी हाशम किदवाई साहब की तहरीर पर जोकि मेरे पास मौजूद है जोकि उन्होंने सी० आई० डी० इंसपैक्टर और एस० पी० को लिख कर भेजी है उसके बमुजिब उन बच्चों की बेल को फौरन कैंसल करके जेल में भेज दिया। इसी तरह से पांच बच्चों को परसों गिरफ्तार किया गया है जबकि अपने मुकदमात की पैरवी करने के लिए गये थे। अब्दुल बासित की बेल कैंसल करके जेल में भेज दिया। अभी युनिवरसिटी के अन्दर एक, एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि 25 ता० को तुम कहां थे और अगर नहीं यहां नहीं थे तो क्यों नहीं थे? उस की वजह बतलावें। यह तमाम चीज जोकि वहां की जा रही हैं बच्चों को हिरासा कर रही है। वह अपने तहफ्फुज की ओर सोचे या अपनी तालीम की तरफ सोचे इस पर आप को गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इस किस्म की हरकतें जो बच्चों के साथ हो रही हैं वह नहीं होनी चाहिएं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मौलवी इसरारुल हक साहब का जिक्र किया जोकि जमीयत के प्रेसिडेंट हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस जमात का सेक्रेटरी हूं मुझे खुद इसरारुल हक साहब ने कहा था कि अगर तुम मि० चागला ने जो आर्डिनेंस जारी किया है उसकी ताईद कर दो तो तुम्हें बहुत कुछ उस से फायदा हासिल हो सकता है। मैं ने मौलवी इसरारुल हक साहब से साफ़ कह दिया कि मैं इस के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता कि मैं अपने

[श्री मुजफ्फर हुसैन]

जाती फ़ायदे के लिए उनके ग्रार्डिनैंस की हिमायत करूं क्योंकि ऐसा करना मेरे नजदीक कौम फरोशी ग्रौर मजहब फरोशी ग्रौर दीनफरोशी होती है जोकि मैं कभी करने को तैयार नहीं हूं। मैं ग्रपने जाती फायदे के लिए इस ग्रार्डिनैंस की हिमायत नहीं कर सकता। मौलाना इसराकुल हक़ ने मुझे तार दिया था जिसमें मुझे कहा था कि उन्होंने मेरा नाम श्री चागला के पास कोर्ट की कौंसिल की मेम्बरी के लिए लिख कर भेज दिया है ग्रौर ग्रगर मि० चागला की तरफ़ से कोई कागज मेरे पास ग्राये तो मैं उस कागज पर ग्रपने दस्तखत कर दूं। ग्रब मौलना इसराकुल हक़ को जो मजहबफरोशी या कौमफरोशी का सिला ग्रापने दे दिया। ग्राप ने उन को मुगल लेन कम्पनी का डायरेक्टर बना दिया ग्रौर उनको ग्रलीगढ़ मुस्लिम युनिवरसिटी कोर्ट का मेम्बर भी नामजद कर दिया है। ग्रब श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो यह कहा कि मौलना इसराकुल हक़ ने जमीयत के प्रेसीडेंट होने की हैसियत से चागला साहब ग्रार्डिनैंस की ताईद की है तो मेरा कहना यह है कि उन्होंने ग्रपने जाती फायदे की बिना पर ऐसा किया है न कि एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसा उन्होंने किया। उनके सामने ग्रपने जाती फायदे का सवाल था इसलिए उन्होंने मि० चागला की ताईद की न कि उन्होंने ग्रापके जाती मामलात की ताईद की।

जहां तक श्री प्रकाशवीर शास्त्री की इस मजम्मत का ताल्लुक है ग्रौर जनरल शाहनवाज खां या हुमायुन कबिर साहब को किसी जमात के मेम्बर होने का जो उन्होंने इल्जाम दिया तो किसी जमात का बहैसियत मुसलमान होने के उनका मेम्बर होना कोई जुर्म नहीं है ग्रौर वह इस बात की दलील नहीं है कि वह हुकूमत की बॉडी के ग्रन्दर रह कर किसी जमात के मेम्बर नहीं रह सकते है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ग्रगर ग्रपनी जनसंघी ग्रौर महासभाई जहनियत के ऐतबार से शाहनवाज पर ग्रौर हुमायुन कबिर के ऊपर यह इलजाम लगा सकते है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हाउस उनको इस बात की इजाजत देगा कि वह इस किस्म की बात करें ग्रौर किसी की जात पर हमला करें ?

मैं ग्राखिर मे ग्रर्ज करूंगा कि मैं श्री यशपाल सिंह के एक एक लफ्ज की ताईद करता हूं ग्रौर ग्राप से गुजारिश करूंगा कि ग्राप चागला साहब को मजबूर करें कि वह ग्रपने इस ग्रार्डिनेंस को वापिस लें।

श्री शिव नारायण (बांसी) : मैं बड़ा ग्रनुगृहीत हूं कि ग्रापने मुझे इस ग्रवसर पर बोलने का ग्रवसर दिया। चूंकि मैं एक टीचर रहा हूं . . . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं ने जब माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाया तो मैंने कहा उस्ताद शिव नारायण।

श्री शिव नारायण : ग्रब ग्राप बजुर्ग है जो भी चाहे कहें।

नेपोलियन जो कि दुनिया का सब से बड़ा कमांडर हुग्रा है उस ने यह कहा था :—

"Those who will obey they can give order."

गत 25 ग्रप्रैल का जो नमूना हमने ग्रलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी में देखा वह निश्चित रूप से इस देश के इतिहास में एक बड़ा गंदा दिन है। जो गुंडेबाजी ग्रौर ग्रनुशासनहीनता उस ग्रवसर पर हमने देखी उससे मारे शर्म के हमारा सिर झुक जाता है। मैं पुरजोर शब्दों में उस की भर्त्सना करता हूं जहां कि इस तरह से वाइस चांसलर को मारा जाये ग्रौर वह तो बच गये बाकी मार डालने में कोई कसर शरारती लोगों ने छोड़ी नहीं थी। इसके विपरीत हमारी संस्कृति हमें क्या

सिखाती है? "ग्रुरी विशम्भरा"। हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह पाठ सिखाती है :-

"मातृवत् परदारेश परद्रव्येण लोशष्वत् आत्मैवत सरभूतेषु या पश्यति सः पंडितः" हमारी नसों में यह संस्कृति विद्यमान है और इसलिए यह जो अलीगढ़ में 25 अप्रैल को अशोभनीय और सर्वथा अनुचित व नग्न चित्र उपस्थित हुआ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं श्री स्वैल से कहना चाहता हूं कि वह अलीगढ़ गये थे कि नहीं? उन्हें अलीगढ़ जाकर स्थिति का पता लगाना चाहिए। अब जो नक़शा वहां पर 25 अप्रैल को हुआ उस को हिन्दुओं ने बर्दाश्त किया क्योंकि हम नौनवाएलैंस के हामी हैं और अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हैं। हम गांधी और नेहरू जी के बताये हुए मार्ग पर चलते हैं इसलिए हम ने वह सब बर्दाश्त किया। यहां पर उधर से जो कम्यूनलिजम को उभारने वाली स्पीचैंज हुई उनसे मुझे बहुत दुःख पहुंचा है।

जहा तक आर्डिनेंस का सवाल है उस में कोई ऐसी खराबी नहीं है जिसके लिए उधर से चंद दोस्तों ने इतना वावैला मचाया है। गवर्नमैंट के पास आर्डिनेंस लाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था वह इसे लागू करने को मजबूर हो गयी थी और यह आर्डिनेंस मेरी समझ में उसने उपयुक्त अवसर पर जारी किया। श्री मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि वहां तूलबा ने जो किया वह एक मामूली बात थी लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या किसी आदमी को जान से मार डालने की कोशिश करना एक साधारण बात है? अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वय एक जज रह चुके हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि क्या यह एटैम्प्ट टू मर्डर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत नहीं आता है और क्या यह कोई साधारण बात है? वाइस चांसलर ने चिट्ठी लिखी और गवर्नमैंट ने स्टैप लिया। चागला साहब ने कौन सा गुनाह किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उनको भी आपने बड़ी गालियां दी थी। आज जब चागला साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं तब भी आप आज उन को गालियां देते हैं। इस तरह से मुसलमानों को गालियां देना ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि आप छागला साहब को गालियां नहीं देते हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को गालियां देते हैं, हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, जो कोई भी हमारा रिप्रिजेंटेटिव यहां बैठता है, उसको आप गालियां देते हैं। यह बड़े ही दुख की बात है।

हमें मौलाना हिफजुर्रहमान साहब जैसा मुसलमान अलीगढ़ ने पैदा कर के दिया उस पर गुमान है। जब वह हमारे यहां आते थे तो हिन्दू भाई भी और मुसलमान भाई भी उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। हमें ऐसे मुसलमान चाहिये, डा० जियाउद्दीन जैसे मुसलमान चाहिये। हमें औरंगजेब नहीं चाहिये, हमें अयूब नहीं चाहिये। जनरल अयूब आज पाकिस्तान में औरंगजेब का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में बन्द कर दिया है (इंटरप्शंस) जब शिष्य गुरू के पास विद्या हासिल करने के लिये जाते है तो उन को अपने धर्म का भी पालन करना चाहिये। वह उन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में से हम को अच्छे पंडित मिलें, हमें बड़े विद्वान मिले, हमें मैथेमैटीशियन मिलें, ऐसे लोग वहां से निकले जो कि भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले हों। इंडियन कल्चर में विश्वास रखने वाले हों। आज हम को सही मानों में आदमी चाहियें।

आप देखें कि काश्मीर में क्या हो रहा है। काश्मीर के हिन्दू और मुसलमान युनाइटेड हैं और दोनों मिल कर पाकिस्तानियों का मुकाबला कर रहे है। उन्होंने इस एकता को रिपीट किया है। जो उनको मारने के लिए आते हैं, उन को उन्होंने बदले में मारा है। वे भाई-भाई की तरह

[श्री शिव नारायण]

रह रहे हैं। उन्होंने हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।

मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो इस आर्डिनेंस का विरोध करते हैं, वे अलीगढ़ जा कर देखें, हमारे बदरुद्दुजा साहब वहां जा कर देखें, बनर्जी साहब जा कर देखें कि क्या हालत है और हमने कितना टालरेट किया है। वहां के नग्न चित्र को मैं यहां बयान नहीं करना चाहता हूं, 25 अप्रैल, को जो कुछ वहां हुआ, उस को मैं बयान नहीं करना चाहता हूं, एग्जैमिनेशन हाल में जो घटनाय घटी हैं, उन को मैं बयान नहीं करना चाहता हूं। हमारे हरवानी साहब ने सब हालात बयान नहीं किये हैं। उन पर भी हमला किया गया था। वह बच गए। अलीगढ़ पास में ही है, और मैं किसी को भी दावत देता हूं कि वह जा कर वहां देख ले, जिसकी तबीयत हो, अलीगढ़ जा कर देख ले और हालात का खुद जायज ले ले। वह जगह कोई दूर नहीं है। शिक्षा संस्थाओं को जिन को हम 95 प्रतिशत पे करते हैं, वह पब्लिक मनी है। उस में हर एक आदमी का योग दान होता है, हर एक आदमी जो टैक्स देता है, उस में उसका योगदान है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का इस में योगदान रहता है।

हमारे भाई फ्रैंक एंथनी साहब ने बड़ा जोर का भाषण किया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं ब्रिटिश वैस्ट-इंडीज में पैदा हुआ था और मिशन स्कूल में पढ़ा हूं। मैं क्रिश्चियन कल्चर को जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भाषण उन्होंने किया वह उचित नहीं था। बिल्कुल अनुचित था। उन से हमें इस तरह के भाषण की उम्मीद नहीं थी। वह शिक्षा संचालक हैं। बड़ी बड़ी संस्थायें वह चलाते हैं।

हमारे यहां भी एक मुसलमान हैं जोकि कालेज चलाते हैं। उन्होंने मुझ से कहा कि उन्हें पी० एस० पी० वाले कहते हैं कि वे चुनाव के लिए खड़े हो जाए। मैं ने उन से कहा कि वह बस्ती में वही काम कर रहे हैं जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में किया। वह इंस्टीट्यूट में अपनी सारी कमाई दे गए हैं। इस तरह के मुसलमान हमें चाहियें, इस तरह के बड़े बड़े पंडित हमें चाहियें। वे मुसलमान हमें चाहिय जो कुरान की सही सही तालीम दे सकें। सही सही तालीम दे कर जो कनवर्ट कर सकें। इस तरह के मुसलमान आपको चाहियें कि आप पैदा करें।

जहां तक गुंडा गर्दी का सम्बन्ध है, वह चलने नहीं दी जा सकती है। यूनिवर्स्टीज में अगर गुंडागर्दी होगी तो यूनिवर्स्टी का खुदा ही हाफिज। एक नहीं अगर बावन यूनिवर्स्टीज हों तो भी हम को उन को सीधे रास्ते पर लाना होगा और गुंडागर्दी का सफाया करना होगा। इसको हम टालरेट नहीं कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि शिक्षा संस्थायें उत्तम शिक्षा विद्यार्थियों को दें, सुयोग्य औलाद पैदा करें, बढ़िया हिन्दुस्तानी पैदा करें सच्चे हिन्दू मुसलमान पैदा करें, उन में एकता की भावना कूट कूट कर भरें। हमारे सभी जितने विश्वविद्यालय हैं वे ऐसे ही हों।

मेरे मित्र ने लखनऊ, उड़ीसा और न जाने किन-किन विश्वविद्यालयों के बारे में कहा है कि वहां भी गंडागर्दी हुई है। लेकिन में उन को बतलाना चाहता हूं कि वहां कहीं भी वाइस चांसलर को मारने की कोशिश नहीं की गई है, मर्डर करने की

एटेम्प्ट नहीं हुई है । वहां पर उनकी मोटर को फूंका गया है, उन के शीशे तोड़े गए हैं । यह सब हुआ है और यह जायज भी हो सकता था लेकिन एटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ है । अलीगढ़ में हमारे अली यावरजंग साहब को मर्डर करने की कोशिश की गई है । हमारे शास्त्री जी ने कहा कि आप अली यावरजंग के साथ हैदराबाद का बदला लेने की कोशिश करना चाहते थे । वह नक्शा आप के दिमाग में था । यह आपकी स्पीचिज बता रही हैं । उन को सुन कर पता चल जाता है कि आपके मन की भावना क्या है । **ए मैन इज नोन बाई दी सोसाइटी ही कीप्स** । आप इस तरह के ही दिखाई देते हैं । यह आपके भाषण से स्पष्ट हो गया है । हम संतोष करते हैं । हम जानते हैं कि किस तरह से टालरेट किया जाता है । हम टालरेट करते हैं । क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात । हम क्षमा करना जानते हैं और क्षमा करते भी हैं । हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ईमानदारी के साथ, नेक नीयती के साथ हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों को प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है । नेहरू और गांधी की प्रतिज्ञा को हम भूलने वाले नहीं हैं । हम उनके फालोअर हैं । मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हम उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने में किसी से पीछे नहीं है और न हो किसी से पीछे रहेंगे । मैंने उर्दू को प्रोटेक्शन के लिए कहा है, इनकी संस्कृति को प्रोटक्शन के लिए कहा है । और आप क्या चाहते हैं ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश काउंसिल में बोलते हुए मैंने उर्दू का समर्थन किया था । सियासत अखबार में उनके बारे में एक बड़ा कालम निकला था । मुझे उन अखबार वाले ने बताया था कि शिव नारायण तुम को उतना पता है जितना हमको भी पता नहीं है ।

मैं चाहता हूं कि हम ईमानदार हों । हमारे देश में प्रेम की भावना पैदा हो । देश के रक्षक पैदा हों । हमारे कमांडर्ज जो फ्रंट पर मारे गये हैं, वे देश की रक्षा करते हुए मारे गए हैं, उन्होंने देश की खातिर कुर्बानी दी है । उन में मुसलमान भी थे । आज हमें वैसे लीडरों की, कमांडरों की जरूरत है । वैसे लीडर हमें चाहिये । ऐसे नहीं चाहिये जो हमारे बीच में झगड़ा पैदा करें । डिवाइड एंड रूल की पालिसी को आप सलाम बोलिये । मुसलमान कौन होता है । मुसल्लम ईमान वाला मुसलमान होता है । वैसा मुसलमान हमको चाहिये । मुसल्लम ईमान वाला चाहिये । मैं छागला साहब का समर्थन करता हूं कि उस में जो उन्होंने किया है । वह बड़े विद्वान मिनिस्टर हैं, बहुत बढ़िया मिनिस्टर हैं । इन्होंने हमारे देश का गिर, यू० एन० ओ० में जा कर और हमारे केस को रख कर, ऊंचा किया है । हमें ऐसे ही योग्य और पढ़े लिखे मिनिस्टर की जरूरत थी । इनको कुछ माननीय सदस्यों ने कानून बताये हैं । इनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये कानून नहीं जानते हैं । ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं । ये कानून के पंडित हैं । इतने बड़े पंडित को हमने यहां बिठा रखा है । चूंकि ये मुसलमान हैं, इस वास्ते इन पर छींटाकशी की जाए यह ठीक नहीं है । ये ऐसे वैसे मुसलमान नहीं हैं, ये पक्के नेशनलिस्ट मुसलमान हैं । मौलाना आजाद और रफी अहमद किदवई की जगह यह काम कर रहे हैं । सही आदमी को हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है ।

मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं करता हूं । लेकिन मैं हर मुसलमान से अपील करता हूं कि वह मुसल्लम ईमान वाला आदमी बने और ऐसे ही मुसलमान व हमें पैदा कर के दें । जिन यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियां होती हैं, काम ठीक तरह से नहीं चलता है, उनको हम टालरेट नहीं कर सकते हैं । उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा और जरूरत हुई तो उनको बन्द भी किया जा सकता है । अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहां डिसिप्लिन

[श्री शिव नारायण]

रहेगा । तब देश को सम्भालना मुश्किल होगा । इस देश को सम्भालना कमिंग जैनरेशन का काम है । उसको ही यह जिम्मेदारी लेनी है । वही इस मुल्क के भाग्य को बनाने वाली है । हम तो पचास वर्ष के ऊपर हो गए हैं । हम लोग तो टिकट कटा चुके हैं । नौजवानों के हाथ में ही भारत का भविष्य है । हमारा तो चला चली का वक्त है ।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह एक बहुत ही कम्प्रिहैंसिव बिल लायें फिर चाहे वह हिन्दू यूनिवर्सिटी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस मुल्क में हम प्रेम की शिक्षा चाहते हैं, इस मुल्क में हम चाहते हैं कि एकता कायम हो ।

इन शब्दों के साथ मैं जो आर्डिनेंस जारी किया गया था उस का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय दो तकरीरें बहुत जोशीली हो चुकी हैं । अब सुभद्रा जोशी जी सुरीली कोई तकरीर दें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ बेइंसाफी सिर्फ यह है कि इनके बाद मुझ को बोलने के लिए कहा गया है ।

श्री डा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : यू० पी० के बाद यू० पी० ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मेरी जो दिक्कत है उसका एहसास आप कर सकते है ।

हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने हम लोगों को बताने की कृपा की है कि डा० सैयद महमूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट थे । ईश्वर जानता है, मैं तो नहीं जानती हूं कि प्रकाशवीर शास्त्री जी कहां की पैदाइश हैं । जितना जहर उन्होंने अपने भाषण में उगला है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और शिक्षा मंत्री जी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के बाहर वह कितना जहर उगलते होंगे और कितनी गलत बातें कहते होंगे ।

आज जो आर्डिनेंस हमारे सामने पेश है और जो बिल हमारे सामने पेश है उसकी बदकिस्मती से उसका पुराना दुखदायी इतिहास है, कई वर्षों से । जिस तरह से और कई व्यक्ति शिकार हुए हैं, उसी तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी एक टारगेट बना दिया गया है कुछ लोगों का । हमारे माननीय यशपालसिंह जी की बहादुरी की मैं तारीफ करती हूं । उन से मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो बात वह तमाम हिन्दुओं के बारे में कह रहे थे उसको एमेंड करके यह कह दें कि कुछ फिरकापरस्त लोग ऐसे हैं जो यह सब बात कहते हैं और उन फिरकापरस्तों की तादाद बहुत कम है, वे मुट्ठी भर हैं और ज्यादातर हिन्दुस्तान के लोग चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, फिरकापरस्त नहीं हैं और वे इन फिरकापरस्त भाइयों की बातों को पसन्द नहीं करते हैं । कुछ मुट्ठी भर लोग हमेशा हर एक के खिलाफ इलजाम लगाते हैं । हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने अभी जनरल शाहनवाज खां के बारे में कहा । चूंकि समय कम है, इस वास्ते मैं उन में जाना नहीं चाहती हूं । प्रकाशवीर शास्त्री जी के इतिहास से हम वाकिफ नहीं है लेकिन जनरल शाहनवाज खां के इतिहास से दुनिया में कौन वाकिफ नहीं है ? कौन उनको नहीं जानता है । हमारे माननीय सदस्य तो इस में विश्वास करते है कि कीचड़ को इतना उछालो, इतना डालो कि चाहे कोई कितना भी यत्न करे, कितना झाड़े, कितना पोंछे, थोड़ा न थोड़ा लगा ही रहे ।

आज उनकी सहायता, उनकी स्पोर्ट छागला साहब को मिली है । इसको छागला साहब का सौभाग्य समझिये या दुर्भाग्य । पर मैं छागला साहब को यकीन दिलाना चाहती हूं कि वह दिन दूर नहीं जब यहां

प्रकाशवीर शास्त्री जी यही हाल चागला साहब का न करें जो हाल आज वह हुमायूं कबीर साहब का और जनरल शाहनवाज साहब का इस हाउस में करते हैं। क्या उन्होंने यही हाल हमेशा मौलाना आजाद का नहीं किया? जब चागला साहब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो प्रकाशवीर जी के खयालात के जो अखबार हैं उन्होंने हजार हजार गालियां चागला साहब को दीं और कहा कि शिक्षा मंत्री एक मुसलमान को बना दिया गया है। यह हिन्दुस्तान की सरकार ने अन्याय का काम किया है।

श्री बड़े (खारगोन) : मौलाना आजाद को किस ने गाली दी?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस वक्त श्री चागला का जो बिल पेश है मैं उस का दिल से अनुमोदन करती हूं। पर मैं उन से यह कहना चाहती हूं कि जो मुबारक कदम उन्होंने आज उठाया वह अच्छी नियत से उठाया है, अगर उस में कोई गलती रह गई हो जैसा कि शिक्षा के बड़े बड़े एक्सपर्ट और एक्सपीरिएन्स्ड लोग कल कह रहे थे, तो बिल की वह कमी दूर होनी चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जो एश्योरेन्सेज श्री चागला ने दिये हैं उनका वह आदर करेंगे, उन का हिन्दुस्तान की सरकार आदर करेगी, पूरी कैबिनेट उन का अनुमोदन करेगी और इस विश्वास को श्री चागला बिल के रूप में सदन के सामने लायेंगे। मैं उन के इस कदम का अनुमोदन करती हूं। मैं श्री चागला से दरख्वास्त करूंगी कि जो बहादुरी उन्होंने दिखलाई है, उन ताकतों को दबाने में, चाहे हम उन को रिएक्शनरी कहें चाहे कम्यूनल कहें, कुछ भी कहें, जो उन को समझ में आया उन्होंने किया, वह उस कदम को आगे और आगे ले जायें।

आज हमारे कालेजेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल में, चाहे वह हिन्दू यूनिवर्सिटी कहलायें चाहे हिन्दू यूनिवर्सिटी न कहलाये साम्प्रदायिकता के लिये अवसर है। आज सरकारी कर्मचारीगण के लिये आर० एस० एस० में जाना मना नहीं है। सरकारी कर्मचारी, चाहे वह अध्यापक हों चाहे दफ्तरों में काम करते हों, आज कांग्रेस के मेम्बर नहीं बन सकते, सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर नहीं बन सकते, कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर नहीं बन सकते, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेम्बर बन सकते हैं। पुलिस के लोग भी बन सकते हैं और अध्यापक भी बन सकते हैं। (*Interruptions*) हो सकता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लोगों ने, विद्यार्थियों ने, टीचर्स ने आपस में मिल कर ऐसे काम किये हों, चाहे उसे फिरकापरस्ती समझा जाये चाहे पार्टीबाजी समझा जाय, उन्होंने एक दूसरे को पीटा हो। लेकिन क्या हमारे सामने ऐसे नमूने नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी और स्कूलों के टीचर और लड़के मिल कर दूसरे लोगों को मारने और पीटने का रोज काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। मैं श्री चागला से बहुत आदर से कहना चाहती हूं कि दूसरा कदम वह शीघ्र उठायें और कम से कम अपने अध्यापकों के लिये एक ऐसा सर्कुलर निकालें कि कोई किसी भी फिरकापरस्त जमात में, चाहे वह कल्चरल कहलाये चाहे वह पोलिटिकल कहलाये, नहीं जा सकता है। यह कदम मंत्री महोदय को जल्दी से उठाना चाहिये।

दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस आर्डिनेन्स के पीछे इतना बड़ा इतिहास पड़ा है, और खास कर जब श्री प्रकाशवीर शास्त्री जैसे और दूसरे लोग जहर उगल उगल कर श्री चागला को सपोर्ट करने लगे तो उन के दिल में गलतफहमी हो जाना मुमकिन था। आज मैं भी हिन्दू हूं और मैजारिटी कम्यूनिटी को बिलांग करती हूं। आज मैं कहना चाहती हूं सदन से और दूसरे लोगों से कि हम लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं यहां पर मुस्लिम फिरकापरस्ती या ईसाई फिरकापरस्ती या क्रिश्चियन फिरकापरस्ती, किसी की भी हामी नहीं हूं। पर जिन लोगों की गिनती

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कम है, चाहे कितना ही अच्छा वातावरण हो, उन के दिल में हमेशा शक बना रहता है, एक डर बना रहता है । इस में उन लोगों के साथ न्याय होता है या अन्याय होता है इस बात का सवाल नहीं है । सिर्फ नम्बर की कमी की वजह से ही डर बना रहता है । जब डर बनता है तो उस की वजह से वह सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा हो कर वह अपने को आर्गेनाइज करते हैं । कभी कभी वह बहकाये जाते हैं, कभी कोई गलती भी कर लेते हैं, परन्तु हमारी कम्यूनिटी जो कि मैजारिटी कम्यूनिटी है, हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हिन्दू फैले हुए हैं, उन से मैं कहना चाहती हूं । यह मैं उन से हिन्दू और मुसलमान के नाम से नहीं कह रही हूं बल्कि कहने की बात है इसलिये कह रही हूं कि आप कितने ही मुसलमान वजीर लायें, कितने ही सिख वजीर लायें, कितने ही ईसाई वजीर लायें, लेकिन हिन्दुस्तान के कोने कोने में आखिर वह मुट्ठी भर रहेंगे । इसलिये हम लोगों का दिल बड़ा होना चाहिये, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिये । हमारा फर्ज है कि हम माइनारिटी कम्यूनिटीज को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को, जिन को फिर्कावाराना जमातें हिन्दुस्तान का नागरिक मानने को तैयार नहीं हैं, भरोसा दिलायें और उन में विश्वास पैदा करें कि हमारी मैजारिटी कम्यूनिटी ज्यादा जिम्मेदार है । इसलिये मैं चागला साहब से कहना चाहती हूं कि जब वह बिल को सदन के सामने लायें—मैं कम हक या ज्यादा हक देने की बात नहीं कह रही हूं—तो उस में इस बात का खयाल रखा जाये कि सिर्फ इन्साफ किया ही न जाये, बल्कि माइनारिटी कम्यूनिटी सोचे कि उन के साथ इन्साफ हो रहा है, उन्हें इस बात का इत्मीनान हो कि उन के साथ बेइन्साफी नहीं हो रही है ।

यहां पर कल चूंकि यह बात कही गई कि क्या हिन्दू कल्चर है, क्या मुसलमान कल्चर है और क्या हिन्दुस्तानी कल्चर है । मैं हिन्दू और मुसलमान कल्चर की बात नहीं कहती । मैं चाहती हूं कि हमारे यहां के लोग अपने आप को हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र कहने के बजाय इन्सान कहा करें । जिस दिन ऐसा हो जायेगा वह दिन हिन्दुस्तान और दुनिया के लिये बहुत बड़ा दिन होगा । मैं किसी कल्चर की बुराई नहीं करती, लेकिन क्या हमारे मुंह से शोभा देता है कि जब मुसलमान का सवाल हो तो हम मुस्लिम कल्चर नहीं है यह बात कहें और जब हिन्दू का सवाल हो तो हम हिन्दू कल्चर की बात कहें । क्या हम को इस तरह से कहना चाहिये । क्या हम माइनारिटीज से कहें कि यहां न ईसाई कल्चर है, न मुस्लिम कल्चर है, न सिख कल्चर है, यहां सिर्फ इंडियन कल्चर है । और फिर अक्सर यह देखने में आया है कि अगर पूछा जाता है कि इंडियन कल्चर क्या है तो कहा जाता है कि हिन्दू कल्चर । इंडियन कल्चर की डेफिनिशन हिन्दू कल्चर मुट्ठी भर फिर्कापरस्त लोग देते हैं । मैं ने श्री यशपाल सिंह जी से कहा कि वह सारे हिन्दुओं का नाम लेने के बजाय मुट्ठी भर फिर्कापरस्त लोगों और फिर्कापरस्त जमातों का नाम लें क्योंकि जब ऐसे लोग प्रचार करते हैं तो जिन लोगों की कम गिनती है उन के दिल में बहुत शक व शुबहा आने लगता है । जब मैं यह बात सदन में कह रही हूं कि सारे हिन्दुओं का नाम यहां पर न लिया जाये तो एक बात माइनारिटी कम्यूनिटीज से भी हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूं । मैं उन से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इस ट्रैप में न आयें । आज हम लोगों को, कांग्रेस के सदस्यों को, हिन्दुस्तान के लोगों को, हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को, इस चीज का एहसास है कि माइनारिटी की जिम्मेदारी उन के ऊपर है । वह लोग माइनारिटी की मुसीबतों से वाकिफ हैं और उन के दिल में जो शक व शुबहा है उस से वाकिफ हैं । माइनारिटी कम्यूनिटीज को भी होशियार होना चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि

वह अपने आप को मुसीबत में डाल लें । जब एक आदमी बीमार होता है तो बहुत से डाक्टर जमा हो जाते हैं । कोई कहता है कि ऐलोपैथिक इलाज करो, कोई कहता है कि हकीम का इलाज करो, कोई कहता है कि टोना टोटका करो, कोई कहता है कि झाड़ा फूंका करो । जब इतने डाक्टर राय देते हैं तो मरीज के लिये बड़ा नुकसान हो जाता है । माइनारिटीज से मैं निवेदन करूंगी कि जहां वह हिन्दुस्तान की और बातों को सहन करते हैं, अगर श्री चागला ने पहला कदम फिर्कापरस्ती खत्म करने के लिये उठाया है, तो उन को उस को भी सहन करना चाहिये । भले ही माइनारिटीज के दिल में इस बारे में कोई डर या शक हो, मेरे दिल में कोई शक नहीं है । अगर उन लोगों के दिल में ऐसा खयाल है कि इस में कोई गलती है तो भी मैं उन से कहूंगी कि वह तो भी इस के लिये श्री चागला को मुबारकबाद दें और श्री चागला के दूसरे कदम का इन्तजार करें, जब वह दूसरे स्कूलों से, दूसरे कालेजेज से दूसरी यूनिवर्सिटीज से फिर्कावाराना चीजों को खत्म करने के लिये अपने यहां से एक सर्कुलर निकालेंगे कि कोई टीचर, कोई अध्यापक आर० एस० एस० का मेम्बर नहीं बन सकता है जो कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं समझता है । जब उन लोगों को वह ऐसी जमातों में जाने से मना करने के लिये आगे आयेंगे तब मैं फिर उन को दुबारा मुबारकबाद दूंगी ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, आज आप ने मुझे इतनी जोशीली स्पीच होने के बाद आखिरी मौका दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : बाज वक्त जो अच्छे बोलने वाले होते है उन को आखीर में रखा जाता है ।

श्री बड़े : इस के वास्ते मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि मेरी बहन श्रीमती सुभद्रा जोशी का भाषण होने के बाद आप ने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि पिछले चार सालों से जब जब मैं उन का भाषण सुनता हूं तो उस में आर० एस० एस० और फिर्कापरस्ती के खिलाफ बोलने के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है । इसीलिये मैं उनका भाषण हमेशा बड़े गौर से सुनता हूं । मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर दरअस्ल हम में कोई बुराई है तो हमें वे देश से बाहर निकाल दें । हम वहां जाने के लिये तैयार है । लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आखिर आर० एस० एस० ने उन का क्या नुकसान किया है ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सम्बन्धी आर्डिनेन्स और बिल जो माननीय मंत्री महोदय लाये है मैं उस का समर्थन करता हूं । और उस आर्डिनेन्स के विरोध में जो प्रस्ताव श्री यशपाल सिंह ने रखा है उस का विरोध करता हूं । श्री चागला को धन्यवाद इसलिये देता हूं कि वह आज अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे है । इस अग्नि परीक्षा में ही उन्हें थ्रेटनिंग लेटर्स आते है और कहा जाता है कि :

"Mr. Chagla and Mr. Ansar Harvani and a few others may be regarded as leaders of the neo-nationalists or Sangh nationalists."

ऐसा संगीत सा बनता है कि वह संघ के मुस्लिम है, संघ के नेशनलिस्ट्स है । उन को थ्रेटनिंग लेटर्स आते है कि हर तरह के परिणामों के लिये तैयार हो जाओ । इतना ही नहीं, मुस्लिम पेपर्स जो है उन में भी इसी तरह की बातें लिखा होती है :

"Mufti Atiqur Rehman, Working President of the pro-Congress Jamiat-ul-Ulema-i-Hind has in a statement threatened that if any change was made in the AMU constitution, Indian Muslims 'would resist it with their full strength'. The Jamiat organ Al Jamiat has voiced similar views

[श्री बड़े]

and has said (May 14) that Indian Muslims 'would not allow the AMU to be sacrificed at the altar of secularism'. The Daily Dawat of the Jamaat-e-Islami has asked the University to stop taking grants from Government and then get ready to fight the changes that are going to be made in its Islamic character."

13·30 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि आप सन् 1967 में जब वोट मांगने आवेंगे तो मुसलमान आप को एक भी वोट नहीं देंगे । कांग्रेस को आख खोल कर और कान खोल कर सुनना और देखना चाहिए कि सरकार एक छोटा सा आर्डिनेन्स लायी उस पर उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि हम सन् 1967 में वोट नहीं देंगे । आप के खिलाफ पत्रों में इस प्रकार के थ्रेटनिंग लेटर आते हैं :

> "The Weekly Siraat from Delhi has sought to hit the Congress party on a tender spot by telling it that this "mischievous" move of Government "will lead to the Congress" doom among Muslims."

तो इस प्रकार के थ्रेटनिंग लेटर पत्रों में आते है । इन से वातावरण को गरम कर दिया जाता है । हमारी बहिन जो तो सदा यही कहती हैं कि आर० एस० एस० वाले या जन संघ वाले ऐसे है वैसे है, लेकिन मैं चागला साहब को खातिरी दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी सेशनलिस्ट विचार की है और जो सेशनलिस्ट है हम उनके साथ है । हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है । हम ने उनके साथ एक देश में जन्म लिया है, हम उनके साथ जियेंगे और उनके साथ मरेंगे । हम उनके खिलाफ नही है । लेकिन जो पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाते है, जो यह कहते हैं कि हम के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान, उन लोगों को हम तो क्या कोई कांग्रेस का मेंबर भी बर्दाश्त नहीं करेगा ।

मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां इस प्रकार के नारे नहीं लगाये गये कि पाकिस्तान जिन्दाबाद, क्या 25 अप्रैल को वहां ऐसे नारे नही लगाये गये कि खून का बदला खून से लेंगे, तुम ने उस्मानिया यूनीवर्सिटी को खत्म कर डाला और अब इसे खत्म करने आये हो ? उनके वास्ते एक अर्थी तैयार की गयी थी । क्या यह बात सही नहीं है । मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का नारा पसन्द करेंगे और अगर वह पसन्द करेंगे तो वह देश के शत्रु है

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : नहीं पसन्द करेंगे ।

श्री बड़े : कम्युनिस्ट सदस्या श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि वहां कोई आर० एस० एस० का भीमसेन नामक व्यक्ति था जिसने ऐसे नारे लगाये थे । उनका सदा यह उद्योग रहता है कि ऐसी बातों के साथ किसी हिन्दू को आर० एस० एस० या जनसंघ का कह कर जोड़ दें । वह कहती हैं कि "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का नारा उसने लगाया । अगर उसने लगाया तो मैं उसको धिक्कार कहूंगा और कहूंगा कि वह हिन्दुस्तान में रहने लायक नहीं है । जो हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि समझते है चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, पारसी हों, सिख हों, कोई भी हों, जो गंगा जमुना को माता समझते हैं, वे हिन्दुस्तानी हैं । और "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का नारा लगाने वाला, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, वह यहां नहीं रह सकता ।

25 अप्रैल को क्या हुआ ? एक बड़ी दुखद घटना हो गयी । कोई 1200 विद्यार्थियों ने अलीयावर जंग को मारा यहां तक कि वह

बेहोश हो गये और उनके शरीर में अनेकों फ्रेक्चर हो गये, बेहोश होने के बाद उनको दो जनों ने बचाया। मैं पूछता हूं कि इसके पीछे कौन सी भावना थी ? इसके पीछे यह भावना थी कि अलीयावर जंग को वहां नहीं रहना चाहिए। वहां के प्रोवाइस चांसलर नहीं चाहते थे कि अलीयावर जंग वहां वाइस चांसलर रहें और मैं ठाकुर साहब को बताना चाहता हूं कि वह थे डा० यूसुफ। उनका इतिहास इस प्रकार है :

"Dr. Yusuf was Reader in History, and Nawab Ali Yavar Jung was Professor of History in Osmania University, Hyderabad in 1947-48. Ali Yavar was a nationalist, Yusuf Hussain was a Razakar leader.

After the Police action, Yusuf Hussain fled to Pakistan and from there went to UNO to plead for independent Hyderabad. Sardar Patel vowed that he shall not come back to India. After the passing of the Sardar, however, this gentleman persuaded New Delhi to let him in. He is said to befurious that Ali Yavar, and not he himself, was chosen as Vice-Chancellor.

उनकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वह वाइस चांसलर बनें और इसलिए उन्होंने मुसलमानों को यह कह कर उभारा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों के हक मारे जा रहे हैं, यह कह कर उसने फिरकापरस्त लोगों को तैयार किया। इन्ही लोगों के मारफत अलीगढ़ पाकिस्तान के लिए जम्पिंग ग्राउंड के रूप में तैयार किया जा रहा है। जैसा कि प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने भाषण में बताया कि जब भारत के खिलाफ कोई बात होती है तो वहां बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वहां एक ऐसा फिरका तैयार हो रहा है, उसको उभारा गया और अलीयावर जंग को मार खानी पड़ी। ऐसी स्थिति में वहां कौन वाइस चांसलर रहने को तैयार होगा। ऐसे अवसर पर चागला साहब का कर्तव्य था कि वह हस्तक्षेप करते, और उन्होंने ऐसा किया। इतना ही नहीं कि इस बारे में चागला साहब को सिर्फ अलीयावर जंग ने ही लिखा है, वहां पर उस समय पी० एन० सप्रू साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा है :

"Shri P. N. Sapru, M.P. and member of AMU Court has said":

"There was a determined effort to assassinate the Vice-Chancellor, and I had not the slightest doubt in my mind that this agitation about 75 per cent was only a camouflage. They wanted to kill the Vice-Chancellor. It was a miracle that he survived. And I was myself save by two prominent members of the Court, Mr. Attiqualla Khan of Allahabad and Mr. Hyder. I shall never forget my debt of gratitude to them."

और आगे अलीयावर जंग ने जो पत्र चागला साहब को भेजा उसमें लिखा है :

"In the course of his letter to Mr. Chagla, Ali Yavar Jung writes:

"Far more important than the question of the physical or spiritual injury sustained by me is the question of the continuing existence in the Muslim University of a well entrenched minority of men with possible ramifications in Aligarh town and elsewhere, who are more than merely communal and have deeply reactionary and fascist leanings. . ."

ऐसा अलीयावर जंग ने लिखा है। इस स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से ही यह आर्डिनेन्स निकाला गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह पहला मौका नहीं है कि पुलिस यूनीवर्सिटी में बुलायी गयी है और न यह पहला मौका है कि यूनीवर्सिटी का कांस्टीट्यूशन ससपेंड किया गया। ऐसा पहले भी हो चुका

[श्री बड़े]

है। मैं आप को एक पत्र में से पढ़ कर सुनाता हूं :

"This is not the first instance of the Police being called into the University campus. It is also not true that the University constitution was suspended for the first time. During Mr. Zaiuddin regime, the Police was called and Mr. Ross Masood accepted the Vice-Chancellorship only after the then constitution was suspended."

इतना ही नहीं। इस विश्वविद्यालय में शिया सुन्नियों का झगड़ा भी हो चुका है। और इसके चांसलर कौन हैं ? वह हैं डा० टी० सैफुद्दीन। श्रीमती सुभद्रा जोशी कहां गयीं, मैं उन को यह बताना चाहता था कि उनके बारे में क्या लिखा गया है :

"Dr. T. Saifudin's advisers have not yet thought fit to condemn the attack by undesirable element of the Aligarh University on the Vice-Chancellor as a result even a person like Mr. Chagla our Education Minister, had to publicly comment on it."

जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी इस को कंडेम नहीं किया, और आगे सुनिये :

"Dr. T. Saifudin went away with his family to Pakistan while Pakistan was attacking Kutch. The Nationalist Bohras under the aegis of Dawoodi Bohra Pragati Mandal telegraphically requested him to return to India; to condemn Pakistani aggression and mobilise Bohra support to the Government. Instead, he issued a firman from Karachi of Barat (Social Boycott) once again under the guise of religion which in effect is ex-communication of members and supporters of the Pragati Mandal . . ."

यह प्रश्न पूछा गया था कि उनको पाकिस्तान गये कितने दिन हुए। उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। यह वह वाइस चांसलर है जो "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाते हैं। अगर उस विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति रहेगी तो सरकार को उसका कांस्टीट्यूशन ससपेंड करना पड़ेगा क्योंकि अलीयावर जंग वहां रहने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि उनको पूरे अधिकार न दिये जायें।

मैं बदरुद्दूजा साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह हिन्दुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यदि वह इसे हिन्दुस्तान ही रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के एलीमेंट को या पाकिस्तान का यहां बीज रोपने वालों को पनपने देने का वायुमंडल यहां नहीं रहना चाहिये। क्या श्री फ्रैंक एन्थोनी यहां पर क्रिश्चयन किंगडम बनाना चाहते हैं ? श्री फ्रैंक एन्थोनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यगण और हमारे श्री बदरुद्दूजा मिल कर जोरदार भाषण देने लग गये और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल की कड़ी मुखालफ़त करने लग गये और उन के भाषणों को सुन कर ऐसा प्रतीत होता था मानों पाकिस्तान और चीन ने आपस में हाथ मिला लिया हो।

श्री आबिद अली जो कि पार्लियामेंट में एक माननीय मेम्बर है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के बारे में कहा है और जोकि हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है। उन्होंने यह कहा है :—

"It cannot be denied that the university had become a hot-bed of communalist and communist activities. This led to the deterioration in the educational standards and consequently the prestige of the university suffered. Some of the recent Vice-Chancellors of the university themselves contributed to this deterioration by their acts of commission and omission.

Mr. Abid Ali said fortunately Mr. Ali Yavar Jang took the initiative to introduce necessary reforms which were long overdue. No one believed that the communalist-communist elements would permit him to proceed unchallenged."

इसी तरह से श्री अलीयावर जंग ने श्री चागला को जो पत्र लिखा है उस में उन्होंने यह कहा है :—

"I left a distinguished career of service to my country to take up my duties at Aligarh, hoping to serve my community in a national context and for high academic aims. I have never touched dirt in my life and I do not wish to go where, evidently, I am not wanted. In any case, I can do nothing there—nobody can—under the Constitution as it exists. Under the circumstances I seek your permission to place my resignation in the hands of the President of India as Visitor."

वहां की हालत कितनी खराब थी यह इसी लेटर से प्रकट हो जाता है जिसमें कि उन्होंने अपना इस्तीफा लिख कर भेजा है । अब मेरे जो दोस्त कहते हैं कि वह तो तुलबा ने थोड़ी गड़बड़ की थी और उसमें कोई खास बात नहीं थी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से गुंडागर्दी करना और वाइस चांसलर को जान से मार डालने की कोशिश करना क्या साधारण बात थी ? क्या हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो नहीं सकता था ? अब चूंकि वाइस चांसलर मुसलमान था इसलिये दंगे नहीं हुए लेकिन अगर उनके स्थान पर कोई हिन्दू होता और वह इस तरह से मारा जाता तो क्या दंगे न हो जाते ? चूंकि श्री अलीयावर जंग मुसलमान थे और यह सारी वारदात मुसलमान तुलबा ने की थी इसलिये उन्होंने सहन भी कर लिया । लेकिन इस से यह तो नहीं समझ लेना चाहिये कि जो कुछ वहां हुआ वह एक साधारण सी बात थी और यह कि गवर्नमेंट को उसे भविष्य में कभी न होने देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिये ?

श्री फ्रैंक एन्थोनी ने यह आर्डिनेन्स न लागू करने के लिए सेक्शन 30 का हवाला दिया लेकिन इस आर्टिकल 30 को प्रीऐम्बिल और दूसरे रिलेटेड आर्टिकल्स को ऐज ए होल अपने सामने रख कर पूरे मामले को देखना चाहिये कि उसका मतलब क्या होता है ?

श्री चागला का जो जजमेंट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट, 1954 के ए० आई० आर० के पैजेज 290–291 पर मौजूद है जिसमें कि यह कहा गया है :—

"In such cases", as Latham C. J. pointed out, "the provision for protection of religion was not an absolute protection to be interpreted and applied independently of other provisions of the Constitution. These privileges must be reconciled with the right of the State to employ the sovereign power to ensure peace. Security and orderly living without which Constitutional guarantee of civil liberty would be a mockery."

उसी के साथ साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्रिश्चयन मिशनरीज द्वारा विद्यार्थियों को क्या सिखलाया जाता है ?

"राम कृष्ण .....मुक्तिदाता नहीं हो सकते क्योंकि सब के सब बुराइयों के वश में लिप्त थे ।"

"वह कृष्ण... चोर था । उस ने कंस के निरपराध धोबी का घात किया । ऐसे देवताओं पर आसरा रखना बड़ी मूर्खता है ।"

[श्री बड़े]

"देवता से लेकर ब्राह्मण तक सब के सब पाप के अधीन हैं ।"

"राम... पापी था । आप मर गया और फिर जी नहीं उठा ।"

इस तरह के क्रिश्चयन मिशनरीज के इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में चलते हैं जिसमें कि हमारे यह आदरणीय दोस्त इंटरैस्ट लेते हैं और चाहते हैं कि वे इस तरह की गुमराह करने वाली शिक्षा यहां के नवयुवकों को देते जायें । वह लोग मुस्लिम माइनारिटी या क्रिश्चयन माइनारिटी के नाम पर इस तरह के जहर उगलने देने की वकालत करते हैं और सरकार पर जोर डालते हैं कि यदि सरकार ने उनको अपने हाथ में लिया, उन पर नियंत्रण किया तो यह माइनारिटी के राइट्स को दबाना होगा । मेरे दोस्त सैकुलर स्टेट होने की बात करते हैं तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में नियोगी कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ साफ़ लिखा है :—

There are two classes of secular states:

(a) those where the very idea of religion is hated and discarded as a dangerous thing; and

(b) where religion as such is respected.

महात्मा गांधी ने भी इस विषय में यह कहा है :—

"The need of the moment is not one religion but mutual respect and tolerance of the devotees of different religions. We want to reach not to a dead level but unity in diversity. Any attempt to root out traditions, effects of heredity, climate and other surroundings is not only bound to fail but is a sacrilege. The soul of religions is one but it is encased in a multitude of forms. The latter will persist to the end of time."

अंत में और अधिक न कहते हुए सिर्फ श्री यशपाल सिंह के बारे में एक शब्द निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने कि इस बारे में बहुत जहर उगला था । उन के बारे में उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि ठाकुर यशपाल सिंह ने संसद् में मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय सम्बन्धी संशोधन विधेयक के बारे में जो अपने विचार प्रकट किये हैं हम उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उसके प्रति अपना घोर विरोध तथा असहमति प्रकट करते है । उन्होंने यह भी मांग की है कि ठाकुर साहब ने अपने उक्त वक्तव्य में हिन्दुओं पर जो मिथ्या और घृणित आरोप लगाये हैं वैसा कर के उन्होंने 90 प्रतिशत हिन्दू मतदाताओं का विश्वास खो दिया है और हम यह मांग करते हैं कि श्री यशपाल सिंह संसद् की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दें ।

अंत में मुझे इतना ही कहना है कि यह आर्डिनेंस बहुत ही जरूरी था लेकिन मेरी राय में अगर वह इसके बजाय अलीगढ़ नेशनल यूनिवरसिटी अमेंडमैंट बिल लाये होते तो अच्छा होता । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी से इस का नाम बदलकर अलीगढ़ नेशनल यूनिवरसिटी रक्खा जाना चाहिये । कुछ लोगों की यह मांग कि उस हालत में बनारस हिन्दू यूनिवरसिटी के नाम में से भी शब्द हिन्दू निकाल दिया जाय मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जब तक हिन्दू रहते हैं और हिन्दुस्तान चूंकि हिन्दू से बना है इसलिये उसका तो बनारस हिन्दू यूनिवरसिटी ही नाम रखना है । लेकिन समय आ गया है जब कि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी का नाम बदल कर अलीगढ़ नेशनल यूनिवरसिटी रक्खा जाय

ताकि वहां पर यह जो रैलीजस और कम्युनल तत्व फैलते है और परवरिश पाते हैं वे पनपना बंद हो जायें और वह नेशनल यूनिवरसिटी के रूप में भविष्य में चलाई जाय ।

ठाकुर यशपाल सिंह ने जो अपना भाषण दिया उसमें 25 अप्रैल को जो वहां कांड घटित हुआ और वाइस चांसलर को मार डालने का प्रयत्न किया गया उसके बारे में उन्होंने कुछ विशेष नहीं कहा, उसको उन्होंने मानों कोई महत्व ही नहीं दिया । इतना ही नहीं बल्कि मेरे एक पूर्व वक्ता ने भी कहा कि वह तो एक मामूली सी बात हो गई । लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या वह 25 अप्रैल की घटना कोई मामूली बात थी ? मैं तो चाहता हूं कि यूनिवरसिटी का कांस्टीट्यूशन सस्पेंड हो और आगे उस युनिवरसिटी का काम जिस राष्ट्रीय आधार पर चलाने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उस पर तेजी के साथ अमल हो । सरकार यह जो अमेंडमैंट बिल अलीगढ युनिवरसिटी के लिए लाई है वह समयोचित है और आज की परिस्थिति में दूसरा कोई चारा नहीं था । मैं श्री चागला को उसे लाने के लिये बधाई देता हूं और श्री यशपाल सिंह ने जो अपना विरोधी प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं ।

Shri Koya (Kozhikode): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I speak in support of the motion that the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon by 10th May, 1966. After hearing the alarming news in today's newspapers, I thought that there would be some restraint in the discussions here realizing that the country was passing through a very serious situation. In spite of the provocations from Members like Shri Prakash Vir Shastri I shall try to be moderate. I shall appeal to the good sense of the majority of the House for the preservation of the rights of minorities which have been guaranteed by the Constitution in unambiguous terms. The hon. Minister, Shri Chagla, who claims to be an ultra-secularist, was in a very pitiable position when he got the support from Jan Sangh and people like Shri Prakash Vir Shastri.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): He got the support from the Congress Members also.

Shri Koya: Many of the Congress Members like Shrimati Subhadra Joshi and experienced hon. Members like Frank Anthony are critical of certain portions. In the Congress Party, persons like Shri Raghunath Singh supported Mr. Chagla and he can be proud of that. While moving for the consideration of the Bill, my hon. friend the Education Minister used very strong words, words which I am inclined to retaliate; but because of the circumstances and the political situation today in the country, I refrain from doing so. He said that the agitation against the Aligarh Ordinance—which was a constitutional agitation and a democratic agitation led by the leaders of the Muslim community including nationalist Muslims —was perverse, misleading and distorted admitted facts. He said that it was an attempt at vilification, defamation and character-assassination. He said that there were pockets of fanaticism, obscurantism and reactionary elements. These were the words used by a Minister of the Cabinet who spoke on behalf of the Government. And many people were asking, who were restrained in moderation, 'How could it be possible that a person like Shri Chagla, an experienced parliamentarian and a Minister speak in this strain?'.

Then, the hon. Minister said that Mr. Ali Yavar Jung was a modern liberal nationalist Muslim, as if his predecessors, namely Badruddin Tyabji, Dr. Zakir Hussain, and Col. Zaidi were not modern and libera' nationalists.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): That does not follow.

Shri R. S. Pandey (Guna): If we praise one person it does not mean that the others are bad.

Shri Koya: I know what it is. I refused to be dictated by him. Shri M. C. Chagla is there, and I think he is capable of defending himself. (*Interruptions*). I do not know why my hon. friend the lady Member should indulge in this kind of running commentary. If she wants, she can ask the Deputy-Speaker to give her a chance to speak.

Shrimati Yashoda Reddy: For the information of my hon. friend I might say that I was not making any running commentary. The interruption that I made was a very legitimate interruption.

Shri Koya: Then, the hon. Minister said something about the incidents of April 25th. He said that there was a conspiracy and there was an attempt to murder, to assassinate the vice-chancellor, there was a conspiracy for that purpose and a coffin had been brought. I wonder whether any conspirators who were making a conspiracy to murder somebody would bring a coffin there openly. So, the whole story looks strange.

The hon. Minister then says that the vice-chancellor has given a report about the incident, and so no inquiry is necessary. He makes the prosecutor and the judge the same man. A Daniel come for judgment! He says that the vice-chancellor says that there was an attempt to murder him, and he would take his word as correct. But I would submit that the vice-chancellor is a party to it, he was involved in the incident himself, and therefore, the vice-chancellor's report should not be the basis for making a judgment. As many of the previous speakers have said, there were similar incidents in other universities also. But we did not hear of this kind of ordinance being promulgated in the case of any other universities. There were incidents in which students were involved in Orissa, and they even occupied the Speaker's Chair in the Orissa Legislature. Again, there was hooliganism in Madras. Nothing was done in all these cases. But so far as the Aligarh Muslim University is concerned, which has got the character of a minority institution, which has got a history, and which is the result of the Aligarh movement, and which has got some emotional background behind it, we find that when such incidents take place, the hon. Minister comes forward with an ordinance whereby he changes the character of the court and the democratic set-up of the whole university is taken away. My hon. friend says that he is a democrat and he believes in a democratic set-up and that this measure is only a temporary measure. Even as a temporary measure, I would submit that there was no necessity for having this ordinance promulgated. He says that if he were to accept the motion for circulation of the Bill or for referring it to a Select Committee the ordinance would lapse. I think the best way in the present circumstances especially in view of the situation that we are passing through is to withdraw the ordinance and restore the *status quo ante* and thus inspire confidence among the minority community and honour the feelings of the Muslim minority in this country.

The hon. Minister also mentioned about Mahatma Gandhi and said he is a secularist. It is really an irony that Mahatma Gandhi who gave up his life for the minority community should have been quoted for the purpose of killing a university belonging to the minority community. After mentioning Mahatma Gandhi's name, my hon. friend criticised people like Dr. Syed Mahmud, a leader who is known as the Gandhi of Bihar and who was throughout with Gandhiji; when Shri M. C. Chagla was only serving British imperialism, Dr. Syed

Mahmud was serving Mahatma Gandhi and he was a nationalist. But now we find that Shri M. C. Chagla is mentioning the name of Mahatma Gandhi to oppose people like Dr. Syed Mahmud. It is really strange that Mahatma Gandhi's name should be quoted in this manner now and then.

The Education Minister quoted from a letter which he had written to Dr. Syed Mahmud. I think that in fairness to Dr. Syed Mahmud, he ought to have quoted also from the letter that Dr. Syed Mahmud wrote to him, but he did not quote from it.

Then he was asking why nationalist Muslims and Muslims of the Congress Party were making a common platform with the Muslim League and the Jamat-e-Islami. He said that the Majalise Mushwarat was formed just to oppose the Aligarh ordinance. By saying so, I feel that he was betraying his own ignorance about the real facts. Majalise Mushwarat was formed about a year back, when the Aligarh question was nowhere, and it was formed under different circumstances and for a different reason. My hon. friend asks how the Muslim Leaguers and the Congress Muslims could work together. But he forgets the facts of history that we the Muslim Leaguers worked with the Congress Party as a joint parliamentary or legislature party and we ruled Kerala for some time. When the Congress people wanted the support of the Muslim Leaguers and could sit with us in the joint legislature party in Kerala and rule Kerala for some time, I do not understand how the Majalise Mushwarat consisting of the Muslim Leaguers and the Congressmen cannot sit together to consider and review the future of an institution to which the Muslims attach very great importance. We have seen that in this House Shri Chagla has been supported by the Members of the Jan Sangh and people like Shri Prakash Vir Shastri and Shri Raghunath Singh. These were the people who were supporting him. There is nothing wrong if the Jan Sangh Members support Shri Chagla. But there is everything wrong if a few Congress Muslims join together with other Muslims to discuss about the future of a university to which the Muslims attach very great importance—I think that this is really strange.

The hon. Minister has said that there were some disturbances and there were some troubles in Aligarh and, therefore, a democratic constitution or set-up for the university was not possible. When he was saying so, I thought that the ghost of President Ayub Khan was speaking in this House, because this was the very argument that President Ayub Khan had been advancing when he wanted to establish the so-called Basic Democracy in Pakistan that because there were disturbances and because there were some troubles, the normal form of democracy could not be worked in Pakistan. My hon. friend the Minister of Education is using the same argument here and saying that because there were disturbances, because of the tactlessness of the vice-chancellor due to which there was some trouble in Aligarh, the best way to deal with the situation in the Aligarh university is to do away with the democratic set-up of the university; this is a remedy which is worse than the disease itself. I am reminded of the story of a man on whose nose a fly was sitting. A friend of his who saw the fly on the nose of that person thought that that person would be offended by the fly; so, he took a sword and killed the fly. What is being done is exactly like that. There was a fly on the nose of the Aligarh University, and Shri Chagla took the sword of ordinance and tried to kill the very good friend.

I submit that this ordinance was uncalled for, and it was unnecessary. The ordinary law would have been enough to deal with the situation in the Aligarh University. We do not for a moment support what happened there on the 25th April. We do not for a moment say that what some mis-

[Shri Koya.]

guided students did there on that day against Mr. Ali Yavar Jung was correct. That does not mean, however, that the whole university should suffer because a few misguided students had committed some mischief. After all, that university has got a tradition; it is a university which had been praised by the leaders like Shri Lal Bahadur Shastri and Pandit Jawaharlal Nehru. Because of a single incident which happened there, which happens in other universities also, to suggest that the university itself should lose its democratic character is something which I cannot understand.

As a result of this ordinance, it not only loses its democratic character but also its Muslim character. For, there is nothing in the ordinance which says that at least one Muslim should be there in the court, even though, of course, Shri Chagla has nominated some of his known yes-men there.

Therefore, I oppose the Bill and I commend my motion for circulating the Bill for eliciting opinion thereon, because the Muslim community, as is evident from the resolutions passed on the Aligarh day is very much agitated over this issue. Especially at this juncture it is no use appealing to Shri Chagla because he has got a personal grudge against Aligarh but I would appeal to the hon. Leader of this House the Prime Minister to see that this piece of legislation is withdrawn.

14 hrs.

Shri Bakar Ali Mirza (Warrangal): Mr. Deputy-Speaker, there was a murderous assault on the Vice-Chancellor, there was great indiscipline among the students, and the Education Minister, Shri Chagla, took certain steps. He suspended some people who were acting as catalytic agents to student indiscipline and rebellion. He had an Ordinance promulgated.

Now, the critics do not say that this act was not in the interest of the discipline of the students. They do not also contend that this is not in the interest of the University or healthy administration of the University. Instead, we talk about minority rights and about killing a Muslim institution. I would like to know why there is this change in emphasis. Do the critics mean that if the same action had been taken in the case of Bombay, Delhi or Calcutta Universities, it would have been justified? Is there no other reason for which they can attack the step taken by the Education Minister? Of the critics I have heard so far, only Shrimati Renu Chakravartty took the stand that it was not in the interest of the University to have a nominated court and so on. All the other critics have taken the stand that it was a deliberate step to kill a Muslim institution.

Why is there this shift of emphasis from the academic to the ecclesiastical? Why is it that people are thinking in those terms? For that, we must try to analyse. All the arguments put together amount to this admission that if the step had been taken in the case of any other university, it would not have been so wrong, or so mistaken. That means that Aligarh is a special goose which has to be treated very tenderly because it lays golden eggs. After all, it is an academic question and as such, must be dealt with on academic grounds.

About this reaction, there has been a demand, and I hink Shri Chagla and also the Vice-Chancellor. Ali Yavar Jung, have conceded that demand and given an assurance that the Muslim character of the University will be maintained. I would like to know what do they mean by this 'Muslim character' of the University. Does it mean that the students who come out of Aligarh University are something different, something special, people who are quite different from the products of, say, Bombay, Madras and other Universities. What is this Muslim character?

Granting that there is a Muslim character to the University, there is a Hindu character to Banaras Hindu University. Am I to conclude from that that all the universities like Bombay, Delhi, Madras and others have no character at all? If it is recognised that a particular type of character is to be preserved, then I ask, is it also not of national importance to preserve the Sikh character, the Christian character, the Buddhist character and so on?

Therefore, this whole concept is fundamentally wrong? Of course, Shri Chagla has not said 'Muslim character'. He said 'Muslim culture'. I wonder what is this Muslim culture. Does he mean to say that the culture of Morocco and of Iran is the same? Religion, of course, is the same, but culture is not the same. Then again, do you preserve a particular type of culture by hearding together people of the same community and educating them there? Does that preserve culture or fossilise it? This is not the way to preserve culture at all.

Shri Yashpal Singh mentioned something about the name, because there has been some suggestion about changing the name of the Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University. I will not deal with this question either from the secular point of view or the political point of view; I will deal with it from the academic point of view. When an Agricultural University was formed, a body like the University Grants Commission objected to that. They said that they should adopt some other name,—this is in the report for 1962-63 or 1963-64. Of course, they did not give any reason. I presume, they felt that even by giving a name which is harmless—specially in an agricultural country, probably people would insist on having an Agricultural University—even by giving a name like that there is a certain circumscription of the function of the University. It takes away at least something from the universality of a university. I think that was the reason in their mind when they raised this objection.

When you talk of Oxford, Cambridge, Columbia, Bombay, and so on, you give it a location, but you do not give a character or direction to that university. This is very important, because I think it is time we stopped proselytisation of our universities. After all, people go to a university in search of knowledge, and knowledge has no bounds, it is limitless. If you bind your mind or intellect by however good a chord, however beautiful a chord, you circumscribe it. If you say that the chord is good for protection, even if it is justified, the very process is against the search and seeking of knowledge. Because a university holds a mirror to reality. If you want to see the image correctly, that mirror should be colourless. However faint the tint, however beautiful the tint, to that extent, it distorts the image of reality. Therefore, this name is not a just a name as Shakespeare said, 'What is there in a name?' It has a meaning which works on our minds.

When you talk of Calcutta, Bombay or Columbia, your vision has no horizon. But when you think of Aligarh Muslim University or Banaras Hindu University, the very first thing that enters your mind is that a wall stands before you and your horizon is barred. However good, however sacred it may be, it is a bar to your vision.

It is not that I am against oriental studies or Arabic studies and so on. Have it. But have it in Banaras, have it in Calcutta. Why have it in Aligarh alone? This is search for knowledge. If people think that they can bring a Muslim tradition or Hindu tradition by having confined specialised courses they are mistaken.

Shri Aurobindo was educated in England. He had never been to Banaras or any of the Pandits there. He had all his education in England—school education, university education also. But still he was steeped in Hindu tradition, he was steeped in

[Shri Bakar Ali Mirza]

the learning and philosophy, of the Upanishads, of the Gita. He gave a message to India which the whole of the products of Banaras put together cannot give.

Therefore, I plead that we must reorientate our whole educational policy.

I know that there is a school of old Aligarhians who have got a great sentimental attachment to that university. In fact, there is such a thing as the Aligarh movement. I also know that there are very big names associated with Aligarh as also with Banaras. But, at the same time, I cannot refuse to face the fact that the very foundation of these institutions was revivalism and communalism. They have not directly, but indirectly, helped to separate the communities; and what is worse, build the communal mind, and that is much more dangerous and much more poisonous than any number of riots in the country.

When I say this, some of my friends, especially the intelligentsia among the Muslims ask me to come down to earth. They say all this talk flying sky high is all right. They say, "You know, we do not get admission here and admission there. Here is one institution which really becomes a sort of refuge for us, and you want to destroy that also." They say that for example in the IAS and IFS there are few Muslims and so on. My reply to that is this. First of all, this is a matter for the Education Minister to look into, but even if this is correct. I maintain that it cannot be solved from a communal platform. Communal ills cannot be solved by communal means. Therefore, I am not only against the Jamiat-ul-ulema, Jammat-e-Islami and all that. I am also against the organisation of nationalist Muslims. I submit that I have been sojourning and vagabonding in politics for 35 years, but not even for one day have I been associated with this nationalist Muslim group, because the very concept is of separation. If one is earnest, one has to recognise that even the nationalist Muslim organisation, by its very existence, has given rise and encouragement to communalism.

So, one has to recognise that Muslims are in a minority. (*Interruptions*)

Probably I will lose more votes than the hon. Member, but what I feel I am saying before the House. You can reject it.

Minorities in the world cannot become majority or be equated with majority, whatever the Constitutional safeguards may be. In the final analysis, the minority everywhere depends on the goodwill of the majority. Therefore, it should be their positive policy to maintain that goodwill. You have to select a platform which, if it is shaken, shakes not only the minority but also the majority. I will give you an example. Suppose 10 first class Muslims are denied and ten second class Hindus are selected for any post. Muslims gather together and say that they are being differentiated against, that the Hindus are doing this and that. The very moment you take that stand, you create a wall of opposition because you condemn the whole Hindu community, and that is not correct, cause you condemn the whole Hindu communalist who made the selection. If you drop the Hindu and Muslim part of it and come forward with the proposition that instead of first classes, second classes have been chosen you will find that even member from the Jan Sangh will come forward and support you, because the sense of justice is inherent in us.

Take the example of the Brahmin community. My Muslim friends say that there is injustice here and injustice there. If you leave the riots apart, the Brahmin community has been discriminated against more than any other community in India, in schools, colleges, uiversities, in the Ministry. And what was their reaction? They tried to maintain the goodwill of the majority community; at the

same time, they allowed time to elapse that merit ultimately asserts itself.

Then there is this question of what should be done now. I think a university is a sacred place; a university should not be managed in the way you manage riots elsewhere, imposing martial law etc., because they are all educated people there. So, you must devise some means by which some form of election is permitted.

There is talk about a judicial enquiry. I was against a judicial enquiry in the beginning because it unnecessarily excites, but some remarks have been made by the Education Minister. There has been wrong reporting, political exploitation and all that. When the case is quite clear, why not face the truth and have a judicial enquiry and finish with it?

The question now is: how long is this ordinance or Bill going to last? Shri Chagla should make a firm commitment now that he will bring a regular legislation in the next session or in the Budget session. He gave the example of the Banaras University. No Education Minister can be proud of saying that for seven years a university has been functioning under an ordinance. Therefore, I think he should make a firm commitment.

There are other ways open to the Opposition, they do not think of them because when there was indiscipline among students in Seoul, they dismissed the Education Minister! That is one way of dealing with it.

Therefore, I would request the Education Minister that he should make some firm commitment.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Chagla.

Shri Mohammad Tahir (Kishanganj): I have given notice of a motion for circulation, and I am not given time to speak.

Mr. Deputy-Speaker: Sorry, we have to close by 1.45.

Shri Muhammad Ismail (Manjeri): I gave an amendment.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Koya had spoken on behalf of your party.

Shri Koya: If you had told me that I alone would be called, I would have asked the leader to speak. This is not fair. This is something concerning the minority community.

Shri Muhammad Ismail: Several allegations, injurious allegations, have been made against the Muslim community. I have got the right to speak. It is very unfair.

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry.

Shri Koya: We protest, we go out.

(Shri Koya and Shri Muhammad Ismail left the House.)

14.18 hrs.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I am very grateful to this House for the very large support that has been given to me, to the policy I have enunciated and the action I have taken, and I want to satisfy this House, if I can, if the House will listen to me dispassionately, that such opposition as has been put forward has been based upon misapprehension and misunderstanding.

First of all, let me take Shrimati Renu Chakravartty. She said that from the democratic point of view it was not right to have a nominated court and a nominated executive council. I entirely agree. I would not like any university to be governed by a nominated court and a nominated executive council, but she forgets that this is a temporary, emergency measure, to be replaced as soon as possible by a permanent measure, where there will certainly not be a nominated court and a nominated executive council. The circumstances were such, the court was so constituted, the executive council was so constituted, that it was absolutely necessary to suspend the constitution and to bring in a measure in which there

[Shri M. C. Chagla]

was a nominated court and a nominated executive council.

My hon. friend who spoke just now referred to the Banaras University. Why was it that when the ordinance was passed, we had a nominated court and a nominated executive council, which have lasted from 1958 to 1965?—because it was felt in 1958 that the only way discipline could be restored, administration could be improved, was by means of a compact body of men in whom the Government and the Vice-Chancellor had confidence. Although it was not intended to be permanent, it went on for seven years; it was unfortunate but we have now introduced a Bill. But it had not changed the character of the Banaras University or the courses of studies or the academic atmosphere. Is it suggested that in the last seven years the Banaras Hindu University has not been functioning properly? Has there been any criticism? Therefore, it only affected the administrative structure. I do not know why so much prominence has been given to the fact that there is a nominated court and a nominated executive council. After all they are selected by the Visitor, on the advice of the Education Minister. The House should trust both the Visitor and Education Minister that he will see to it that people who are selected on these bodies are the people who will do their best for Aligarh University.

Then, Sir, I must straightaway reply to my friend, Mr. Anthony because he has raised a question of very great importance. I think we should solve that problem because it affects not only Aligarh University but it affects the whole structure of our society. I am afraid that I am no longer a practising lawyer and perhaps my law has become rather rusty. But still I know a little bit of law, particularly constitutional law. I entirely disagree with him, with his interpretation of the Constitution. Let us look at the Constitution. There is, first, article 30 on which Mr. Frank Anthony has placed such a great reliance. It says:

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

The right that is conferred upon minorities, it is important to note, is to establish and administer educational institutions of their choice. My submission to this House is that Aligarh University has neither been established nor is it being administered by the Muslim community. It is not a minority institution in the sense in which Mr. Anthony suggests. I will give him the reasons. You had first the Muslim college which was founded by Sir Syed Ahmad. Sir Syed Ahmad asked the British Government of those days to establish a university and the British Government in 1920 passed the Act of 1920; the legislature of those days passed that Act and established the University. Therefore, the establishment of the institution was by the legislature and not by the community. Whatever might have been the origin of the Aligarh University, the Aligarh University itself was established by the legislature. Then came the Constitution. Then in 1951 the amending Act made certain alterations. In our own Constitution in the Union List, entry 63, it is provided that Central Universities and other institutions of national importance can be legislated upon by Parliament. Now, I cannot understand how it can be said that the administration is in the hands of the minorities. The administraton of the university depends upon the law. During British times it depended upon this Act. After independence it depends upon the Act, as had been amended by Parliament. Does Mr. Anthony suggest that it is open to the Aligarh University or the Muslim community to change the administration of the university even to the slightest degree and go contrary to what Parliament has laid down? If the minority had the right to administer the Aligarh University, then it can have any administration it liked; it can change the

administration and it can close down the University; it can change the constitution of the court or the executive council. Can it do so? Even the constitution of the court, of the executive council and of the academic council is regulated, not by the minority community but by Parliament.

There is another aspect of the matter which Mr. Anthony has completely forgotten. He has attached great importance to the fact that under the Act of 1920, the British Government, as a concession, said that the court shall consist wholly of Muslims. Now, everybody know that the University is administered by the executive council and not by the court. The court of course is the supreme authority and it is like a show-piece. It meets once a year; lots of people come there and make speeches and pass resolutions. But the day-to-day administration, selection, appointments and so on are carried on by the executive council and it is significant that even in the British days it was not provided that the executive council shall consist only of Muslims. That clearly shows that the British Government did not concede the argument. Although there was no Constitution then the argument is now advanced by Mr. Anthony that the minority has a right to administer this particular institution. I say that this institution was not established by the minority; nor is it being administered or was ever administered by the minority community. That is the legal position as far as article 30 is concerned.

Article 28 (3) lays down that no person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such peron is a minor, his guardian has given his consent thereto, which means that when a State which is a secular State gives aid to an institution you cannot have compulsory religious instruction given to any person. This is the background.

Let us look at the history of what happened. In 1951, because of the Constitution, Parliament amended the Aligarh Act and said that we could not have this provision, that the court shall consist solely of Muslims because article 15 lays down that the State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Therefore no law can be placed on the statute book of India which says that non-Muslims shall be excluded from becoming members of the court. That would be against our Constitution against the secular nature of our country.

Shri Muhammad Ismail: What does he say to article 16(5)?

Shri M. C. Chagla: I shall deal with it. The other change that Parliament made was that such religious instruction can only be on a voluntary basis. We did the same thing with regard to the Banaras Act. Today, no student in Banaras can be compelled to receive religious instruction; he must give his consent to it.

Let me see what 16(5) says; It says that nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion. This does not deal with educational institutions at all. Article 16(5) has no relevance to the argument; that deals with religious institutions.

Shri Muhammad Ismail: Denominational institutions also.

Shri M. C. Chagla: It does not deal with educational institutions; it is dealt with in article 30.

Therefore, there is no substance in that argument.

Shri Muhammad Ismail: Denominational institution or religious institution.

Shri M. C. Chagla: Article 16 deals with equality of opportunity in matters of public employment. Clause (5) of that article reads:

> "Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination."

My reading of this is that the word "denominational" must be read in connection with the word "religious". It deals with religious institutions. In a religious institution you may lay down that the head of a mutt or the head of a temple shall be such and such a person or the head of a mosque shall be a Muslim. That will not offend against the Constitution.

Shri Muhammad Ismail: The wording is "religious or denominational".

Mr. Deputy-Speaker: He has read it.

Shri M. C. Chagla: Perhaps my friend is a better lawyer than I am. But, as I read this article, "denominational" must be read in connection with "religious". It does not deal with article 15 or article 30. Therefore, the position is perfectly clear.

Aligarh University is a national institution, an institution of national importance established by the Legislature and continued by this Parliament. Parliament has got every right to deal with the administration of the University either through an ordinance or by changing the law. It would be a most extraordinary proposition to suggest that this Parliament, this sovereign legislature, has no right to interfere with the administration of the Aligarh University, which is Mr. Anthony's argument. It was never accepted by the British Government, although there was no Constitution. And even in those days, if you look at the despatches—I have gone through the history of this—when the Governor-General sent the despatch to the Secretary of State suggesting the starting of the Aligarh University, it was made incumbent that the doors of the University shall be open to persons of all castes and communities. Even that British Government would not permit a university to be set up, to be financed by Indian money, which would be communal in its character. But, as I said, they did make this concession about the Court, which we could not keep up because of our Constitution.

Shri Muhammad Ismail: The M.A.O. College also had this tradition and rule of admitting members of other communities.

Shri M. C. Chagla: About what happened in 1951, why is it that Mr. Anthony and his friends and supporters have woken up in 1965 to challenge a law that was passed in 1951? And what change has happened after that? The Aligarh University has functioned as it was functioning.

An hon. Member: You were not here at that time.

Another hon. Member: Neither you.

Shri M. C. Chagla: Sir, let me come to the ordinance. It has been said that the ordinance was not necessary. It has been argued that we could have carried on with the ordinary law and that it was not necessary to have emergency legislation. The Vice-Chancellor in emphatic terms said—and I shall read a passage from his letter to me—that it was impossible for Aligarh University to function unless the constitution was suspended, that it was not possible for him to go back and run this institution unless he was armed with emergency powers.

Shri Koya: You could have sent another Vice-Chancellor.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. No interruptions.

Shri Koya: Interruptions are part of the proceedings.

Shri M. C. Chagla: Sir, I will read that passage:

"The recent deplorable events have opened the lid which well-intentioned but temporizing well-wishers had kept from exposure. I invite you to have a look inside, to order a cleanup and to ensure that the University becomes a source of pride to India and to Indian Muslims as a house of learning, culture and progress. This you can do by suspending the constitution of the University in the same way as was done some years ago in the case of Banaras, so that authority can be exercised effectively for bringing about changes which normally would be impeded by vested interests. Under his existing powers no Vice-Chancellor at Aligarh can do anything much within a short time. He is surrounded by many untrustworthy men at different levels who can and do betray him or sabotage his efforts. He could have a comfortable time and lord it over all if he only agreed to let things continue as they are or encourage the ideas which prevail. I could not do this. I left a distinguished career of service to my country to take up my duties at Aligarh, hoping to serve my country in a national context and for high academic ends."

So, this was what he said.

Shri Koya: He wanted to be a dictator.

Shri M. C. Chagla: Sir, the Muslim League is the last body which should talk of dictators.

Shri Muzaffar Husain: Sir, on a point of order....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There is no point of order when he is replying.

Shri Ranga (Chittoor): When he rises on a point of order, how can you, without even hearing him, say that there is no point of order? What is this? Here is a minority and they want to be heard. (*Interruptions*). I cannot be silenced in this manner. I am the Leader of the Opposition here and I have every right to raise an objection.

Shri A. P. Sharma (Buxar): Everybody has a right. Let him sit down.

Shri Ranga: Here is an hon. Member who wants to raise a point of order. (*Interruptions*)

Some hon. Members: Sit down

Shri Ranga: What is this? Don't behave in such a silly and irresponsible manner.

Shri K. N. Pande (Hata): The Leader of the Opposition is behaving like a dictator.

Shri Ranga: When an hon. Member is raising a point of order, you have no right whatsoever.. (*Interruptions*).

Some hon. Members: Sit down.

Shri Ranga: Don't misbehave. You are here to behave properly.

An hon. Member: We will obey only the Chair.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri Muzaffar Husain *rose*—

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajganj): He wanted only to ask some question, no point of order.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

श्री मुजफ्फर हुसैन : आपने अलीगढ़ यूनिवर्सटी के बारे में आर्डिनेंस तो जारी कर दिया । लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि राम सिंह कालेज के कन्हैया लाल

[श्री मुजफ्फर हुसैन]

गर्ग जो प्रिंसिपल हैं और जिन्होंने शिकायत की थी उसके मुताल्लिक भी आपने कोई आर्डिनेंस जारी फरमाया या उस कालेज की तरफ कोई तवज्जह फरमाई ?

An hon. Member: That is a speech.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order.

Shri G. N. Dixit (Etawah): Does the hon. Member know what is a point of order? Is it a point of order? (*Interruptions*).

Shri Koya: He knows only disorder.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order. (*Interruptions*).

Shri Ranga: We have to respect parliamentary practice.

Shri M. C. Chagla: Sir, may I quote from a speech delivered by the Vice-Chancellor as recently as 29th August 1965 to the staff at Aligarh, and he tells us what the ordinance has achieved·

"I do not wish to say anything at this moment about the conduct of any member of the Executive Council, the attempts made to get the Court to reverse the decision of the Academic Council, the unreliability of certain officers and staff which disclosed my correspondence to a certain group, or the involvement of others besides the students in the attempt to coerce the authority of the University into abdication. All I can say is that, with the magnitude and far-reaching ramifications of the event, and its evident planning, it was impossible for the administration of the University to function effectively with the Court and the Council as then constituted."

This is the view of the Vice-Chancellor, Aligarh University, expressed on the 29th August. He continues:

"I had no doubt, and the Government fully agreed, that to enable the executive authority to work, the constitution, in so far only as it affected the exercise of that authority, should be suspended. That is the only facility provided by the Ordinance, and it was as little as was desired and found necessary. Unlike its prototype of Banaras, it contained no provision for the screening of staff which both the Ministry and I regarded as undesirable. It did not touch the basic character of the University and none of its provisions affected the academic autonomy of the University. In addition, the Ordinance was, by the provisions of the Constitution of India, designed to be shortlived. It is largely due to the Ordinance and the smooth functioning of the organs of the University under it that we have been able, despite obstacles, to reopen the University in conditions of comparative order."

This is the certificate of the man on the spot. This is the certificate of the Vice-Chancellor of the university, a certificate both with regard to the necessity of the ordinance and what the ordinance has achieved.

Sir, I have been libelled, vilified, abused and attacked. I do not mind. But I am rather amused when one of the speakers said that I was out to destroy the Aligarh Muslim University, and I seized this pretext to do so. Did I organise the attack on the Vice-Chancellor?

Some hon. Members: No, no.

Shri M. C. Chagla: Was I responsible for this murderous assault?

Some hon. Members: No, no.

Shri M. C. Chagla: Did I foresee that the Vice-Chancellor, whom we had appointed, will be treated in this way? It is even suggested that I had removed Shri Tyabji from vice-chancellorship. Sir, it is too ridiculous for words. Yet, when passions are aroused, people are prepared to say these things. As I said in my opening speech, I was in the sick-bed; I was in hospital when these things happened. Nothing pained me more than to have taken this step. I believe in autonomy; I believe in democracy. I do not like ordinances; I do not like nominated bodies. But I was helpless. When the Vice-Chancellor says, "I cannot function; I cannot go back to Aligarh, unless you pass this ordinance", I have to do it. It is not I who did it. It is the Cabinet which did it; it is the Government which did it; it is the President who proclaimed the ordinance. It seems to be suggested that this was something which I had done individually, personally, out of spite for Aligarh Muslim University. Why should I have spite for Aligarh? What is it that Aligarh had done to me that I should be out to crush it? It is one of the four Central universities. I treat all the universities alike. They are our national universities, and they are our national pride. I make no distinction between Aligarh, Banaras, Delhi and Visvabharati. I want all these four universities to be model universities of India. I want other universities in India to draw inspiration from these universities.

As I said before, and I repeat that and I shall go on repeating it—that these are national institutions; they are not communal institutions. But every university has a character, a personality and an identity. Banaras Hindu University has a character; has a personality. It must be so. A human being has a character. Why is it that I distinguish one from another? Because every individual is unique. God has made everybody unique. Similarly, about these institutions. They have their characteristics. We want to preserve these characteristics. Aligarh has a great past, a glorious past, and we want to preserve the characteristics of the Aligarh Muslim University.

But I do not think it is in the interests of the Muslims themselves to call this university a communal university. I think it is wrong for any community to build a wall round an institution and try to live within that wall. You must keep all the windows open so that fresh air should come in. Otherwise, you become inbred, frustrated and suffer from a sense of inferiority. I have said this to the Muslims, and my friend Shri Syed Mahmud says that I lecture to the Muslims. I do not. I say this to my friends, I am a well-wisher of India. The Muslims must realise—I am sure he does—that this is as much their country as of the Hindus. The Hindus have no right to call this their motherland; the Muslims have as much that right. Their forefathers have lived here; they, the Muslims will die here; and they will be buried or cremated or whatever it may be. I do not see why a Muslim should have the feeling that he is not as much an Indian and he has not as much right in this country as a Hindu has.

My hon. friend Shri Prakash Vir Shastri put a question to me and I must reply to it. I have got the answer. He said that Shri Syed Mahmud in a letter had asked me that there will be serious repercussions in Pakistan because of this ordinance and what reply I gave him. I have got my reply and I think for the sake of the record, I should read it. I said:

> "I am not worried about what reactions there will be in Pakistan by the action that I might take about the Aligarh Muslim University. Nothing that we do here can have a favourable reaction in a country which is determined to be hostile to us and to make fresh inroads into our rights. There-

[Shri M. C. Chagla]

fore, whatever decision I take will be on merits, irrespective of its repercussions in Pakistan or in other countries."

It was then suggested by Shri Syed Mahmud that this will have unfavourable reactions in the Muslim countries like the Middle East. To that, this is what I said in reply:

"I do not think our friendship with the Muslim world will be influenced by the antics of those in power in Pakistan. The Muslim world does not equate religion with nationalism and our friendship with that world is not based on religion but on common political and economic ideals."

So much for the reaction that this ordinance will have on Pakistan or the Muslim world. Then, Sir, a question was raised as to what is the evidence for a pre-planned conspiracy to attack the Vice-Chancellor. Let the Vice-Chancellor speak for himself.

Shri Koya: Sir, I rise to a point of order.

An hon. Member: Keep quiet. (*Interruption*).

Shri Koya: It is my right to raise a point of order. It is my right as a Member of the House to do so. (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. What is the point of order? (*Interruption*).

Shri Koya: They are going on laughing. Can you not control the crowd, Sir? (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. You go on with your point.

Shri Koya: So many people, including very important people, students, leaders, etc., are arrested in Aligarh, on charges of conspiracy for assassinating the Vice-Chancellor, and in connection with the incidents of the 25th April, in Aligarh, and cases are being filed and charges are made against them. If we say anything which will prejudice the cases, those will be taken to court. Parliament, according to the rules, has no right to discuss a thing which is *sub judice*. It will be unfair if we discuss those things, which will prejudice the case and prejudice the judge. Some people are in jail. Bail petitions are pending. This will even affect the bail petitions. This House will be making a very bad precedent if we allow the hon. Education Minister to read those statements which will affect the case. I think there will be trouble and even contempt of court will also arise.

Mr. Deputy-Speaker: Are there cases pending?

Shri M. C. Chagla: As far as I know, so far, no case has been filed. Investigation is not over. If my friend says that any case is pending, I know the doctrine of *sub judice* and I will be the last person to say anything on that. Is there any case pending?

Shri Koya: Many have been arrested.

Shri M. C. Chagla: "Arrested" does not mean pending.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order.

Shri M. C. Chagla: I do not think Parliament is prevented from discussing it; I am not mentioning any names. If a case is pending, even so, this should not prejudice, because there is no mention of any name. After all, members have spoken and charged me with having passed this ordinance. I am only meeting that charge. This is what he says in his letter dated 2nd May:

"I came to know from Col. Zaidi that as long ago as October, 1964, when I accepted your offer of

the Vice-Chancellorship of Aligarh, two local Urdu rags"—that is the only way to describe those newspapers—"published bulletins accusing me of having betrayed, the Nizam and opposed the Ittihad-Ul-Muslimeen and sold Hyderabad and Osmania University to the Hindus and India."

So, from October a sort of *jehad* was started against the Vice-Chancellor for having liberal, modern, national views, for having stood by India in this controversy of Hyderabad and not trying to sell Hyderabad to a foreign power.

This is what the Vice-Chancellor says in his letter:

"This whole experience was a nightmare and I was not sure till the end that I would get away alive. Had it not been for these two remarkable students and presumably also some of their few friends outside and of course, George and Abbas, I would have been killed. I had been told by the boys outside clearly and definitely that it was their intention to kill me and their lathi blows stones, bricks and iron bars had had been aimed at my head deliberately for that purpose. I have been in some similar scenes before, but have never witnessed such fiendish hatred and savagery. I refuse to believe that this was an agitation only against the change proposed in the rules of admission whose purposes had been fully and reasonably explained along with an assurance of gradual application; it was also not some sporadic event. It was too well organised for that."

This is what some of the members of this House are defending and supporting.

Shri Badrudduja (Murshidabad): On a point of order, Sir. He has been a judge of the High Court. Is it pertinent to base all his arguments on the statement of a particular gentleman who has been the object of controversy all round? Throughout he has been basing his judgment and observations and everything relating to the incident and the developments that took place in the University on the statement of a man who is a party to the controversy.

Mr. Deputy-Speaker: What is his point of order?

Shri M. C. Chagla: I was amazed to hear the Vice-Chancellor being described as a party. He was a victim. Can't I get from the victim what he suffered and how people behaved towards him? After all, he is a Vice-Chancellor. He has come from Paris where he was our ambassador; he is a man of high status and dignity for whom we have respect. My friend there may not trust him,, but I do trust him. (*Interruptions*).

The hon. member, **Muzaffar Husain** said that I have displeased 60 million muslims of this country. Who made him the representative of 60 million muslims of India? (*Interruptions*). I refuse to yield, Sir. These are the people who are spoiling the relations between Hindus and Muslims. These are the people who are inflaming communal passions and they have the impertinence to say that they represent 60 million Muslims of India. They do not even represent a few thousands. I have confidence in the Muslim community. They are nationalists; they are patriots (*Interruptions*). What is this blackmail, Sir? He said in this House that they will not vote for the Congress. I would rather that the Congress loses the elections than win with the votes of such people. The Congress is a party, to which I have the honour to belong, stands for certain ideals and principles. We do not sell our ideals and principles to buy votes. If my friend will not vote for the Congress, the Congress will be very happy to do without his votes. (*Interruptions*). I have received hundreds of letters and

[Shri M. C. Chagla]

hundreds of people have come to see me. There was a meeting held in Bihar where people have said, "We are behind you; we stand by you."

Let me conclude on a note of concord and understanding. We are living through very difficult and dangerous times. The enemy is at our door. No; he has entered inside our country. We must present a united front. This is not the time to raise controversies. The ordinance is a small thing. I have promised this House and I repeat this assurance that I shall introduce substantive legislation as soon as possible. But don't let this ordinance grow into something very big. We want today communal harmony and peace. We want the Hindus and Muslims to look upon themselves as Indians and face the aggressor. These hon. members are doing a great harm to the cause of India's unity and national integration. The ordinance was intended for the good of the Aligarh University. The good of Aligarh University is very near to my heart, just as the good of all central universities. The ordinance will not remain longer on the statute-book than is absolutely necessary. I shall introduce substantive legislation as soon as possible. I assure the House that the character, the individuality, the identity, the personality of the Aligarh University, just as that of Banaras or Visva Bharati, will be preserved.

15 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put the motion to the vote of the House.

Shri Yashpal Singh: My Resolution is there.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put the resolution first. The question is:

"This House disapproves of the Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance, 1965, (Ordinance No. 2 of 1965) promulgated by the President on the 20th May, 1965."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Now, there are some substitute motions that have been moved to the motion for consideration of the Bill. I shall put them first. The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th May, 1966."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Amendments Nos. 2, 3, 15, 20 are barred because they are on similar lines.

Now, amendment No. 4 is for reference of the Bill to a Select Committee. I shall put it to the vote of the House. The question is:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of 12 members, namely:—

Syed Badrudduja, Shri R. Muthu Gounder, Shri S. Kandappan, Shri R. K. Khadilkar, Shri C. H. Mohammad Koya, Shri Krishnan Manoharam, Shri Muzaffar Husain, Shri K. Rajaraman, Shri C. L. Narasimha Reddy, Shri Era Sezhiyan, Shri Mohammad Tahir and Shri M. Muhammad Ismail with instructions to report by the last day of the current session." (4)

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Amendments Nos. 16 and 17 are barred because they are also for reference of the Bill to a Select Committee.

Now I shall put the original motion to the vote of the House. The question is:

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We shall take the Bill clause by clause tomorrow. We shall now proceed with the next item on the Agenda—Shri Prakash Vir Shastri—

श्री यशपाल सिंह : मुझ को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए । मुझे मौका न दे कर एक बेइंसाफी की बात की गई है ।

Mr. Deputy-Speaker: I put it to the vote of the House and it was negatived.

श्री यशपाल सिंह आखिर मैंने रेजोलूशन रक्खा है मुझे उस के ऊपर बोलने का मौका मिलना ही चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. You missed the bus.

श्री यशपाल सिंह : मुझे मौका नहीं दिया गया है । यह कैसे हो सकता है ? मुझे उस से वंचित रख कर मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है । ऐसा कर के मेरे साथ बेइंसाफ़ी की गई है ।

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry, Shri Yashpal Singh. Hon Members should be vigilant. Your Resolution was taken up first. When I called Shri Chagla to reply you did not stand up and ask for time for your reply.

श्री यशपाल सिंह आप ने मुझ से पूछा भी नहीं । आपने मुझे कहा भी नहीं । मैंने तीन दफा कहा । आप ने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की । मैं कहता हूं कि मुझे मौका दिया जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: I put your Resolution to the vote of the House. You did vote.

श्री यशपाल सिंह : आप ने मुझे मौका कहा दिया ? मुझे बोलने का मौका दीजिये । आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, हाईहैंडनैस कर रहे हैं । इस पार्लियामेंट के अन्दर मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है ।

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry. You are too late now. You did not ask for time earlier.

श्री यशपाल सिंह मैंने चार दफ़ आप से पूछा लेकिन आप ने मुझे मौका नहीं दिया । यह सब्जीमंडी का कायदा हो सकता है, पार्लियामेंट का नहीं हो सकता है ।

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry. It is over now. You did not ask for time earlier.

श्री यशपाल सिंह आप मुझे बतलायें कि मैंने चार दफ़ आप से पूछा लेकिन आप ने मुझे उस के बाद भी टाइम नहीं दिया । जिस रेजोलूशन को मैंने शुरू किया जब तक मैं उसे वापिस न लूं आप को कोई हक नहीं है कि इस तरह से आप उसे खत्म कर दें ।

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry. Hon. Members should be more vigilant. When I called on the Minister to reply the hon. Member should have asked for time for his reply.

श्री यशपाल सिंह जब तक मैं अपने रेजोलूशन को वापिस न लूं तब तक रेजोलूशन के वापिस होने का सवाल ही नहीं है ।

एक माननीय सदस्य हाउस ने उसे रिजैक्ट कर दिया है ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Sir, this is Parliament and we cannot go on like this indefinitely.

Shri Yashpal Singh: Sir, if you were mistaken, why should I suffer for that?

Mr. Deputy-Speaker: I was not mistaken.

श्री यशपाल सिंह : मुझे आप ने कोई मौका दिया जवाब देने का ? ऐसा कोई कायदा नहीं है कि बगैर जवाब के दिये इस तरह से कोई रेजोलूशन डिस्पोज ऑफ़ कर दिया जाय । मैंने चार दफ़े पूछा, चारों दफे इंकार किया । पार्लियामेंट में रेजोलूशन पेश होते हैं और उन पर जवाब देने का मौका नहीं दिया जाता है । यह कैसे हो सकता है ? गलती आप ने की नतीजा मैं भोगू यह कैसे हो सकता है ? मैंने चार दफ़े पूछा आप ने मुझे कोई मौका दिया ?

एक माननीय सदस्य : डिवीजन क्यों नहीं मांगा ? (इंटरप्शंस)

श्री यशपाल सिंह : मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया लेकिन मुझे लोग दखल दे रहे हैं । मैंने चार दफ़े आप से पूछा । पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस मुझे आप बतला दें । मैं रेजोलूशन पेश करता हूं उस पर तीन दिन तक बहस होती है और आप मुझे उसका जवाब देने का भी मौका नहीं देते हैं ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आप ने मौका नहीं मांगा आपका रेजोलूशन खारिज हो गया ।

श्री यशपाल सिंह जब मुझे मौका ही नहीं मिला तो मेरा रेजोलूशन खारिज कैसे हो गया ?

Mr. Deputy-Speaker: Shri Yashpal Singh should have been more vigilant. When I called the hon. Minister to reply he should have got up and asked for time. You should have made your reply first at that time. Nothing can be done now. Your Resolution has been defeated.

श्री यशपाल सिंह : मैं खड़ा हुआ लेकिन आप ने मुझे मौका नहीं दिया । मैं तीन मर्तबा खड़ा हुआ । मुझ हुडविक कर रहे हैं । आप ने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है । या तो मुझे मौका दीजिये या फिर मैं सेंट्रल हाल में हंगर स्ट्राइक करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कैसे हो सकता है वह तो खत्म हो गया ।

श्री यशपाल सिंह : गलती आप ने की है क्योंकि आप ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया हालांकि मैंने चार दफ़े आप से खड़े हो कर पूछा ।

Shri Koya: Sir, I rise on a point of order.

Shri Paliwal (Hindaun): Sir, I would like to know whether the proceedings of the House will be allowed to go on or one hon. member will be allowed to hold up the proceedings and how long?

श्री यशपाल सिंह : मुझे कोई ऐसा रूल दिखला दीजिये जिसकी कि रू से मुझ को अपने रेजोलूशन पर जवाब देने का मौका न दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ?

श्री यशपाल सिंह अगर आप इसी तरह से चलायेंगे तो मैं आप के खिलाफ़ जो आपने आज किया है उस के खिलाफ हंगर स्ट्राइक करूंगा । आप ने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है ।

Shri Paliwal: Sir, You should call the hon. Member to order.

Mr. Deputy-Speaker: You are disturbing the proceedings of the House, Shri Yashpal Singh.

श्री यशपाल सिंह : जिस रेजोलूशन को मैंने पेश किया है उस पर मेरे बिना बोले हुए आप उसे कैसे खत्म कर सकते है ? मुझे मौका नहीं दिया गया मैं

ने तीन दफे पूछा। यह शीयर इनजस्टिस है मेरे साथ। या तो मुझ को मौका दिया जाय वरना मैं इस चीज को लेकर भूख हड़ताल करूंगा।

Shri Koya: Sir, my point of order is this. According to the Rules of Procedure of this House, it is for the Speaker to call hon. Members to speak and not for the Members to be vigilant. You did not call Shri Yashpal Singh. He has a right of reply. You may go through the Rules of the House.

श्री यशपाल सिंह ताज्जुब की बात है कि आप मुवर को मौका नहीं दे रहे हैं और खुदबखुद उसे कर रहे हैं। न हाउस को मौका दिया गया और न मुझ को मौका दिया गया। यह तो सब्जीमंडी हो गई, पार्लियामेंट न हुई।

Mr. Deputy-Speaker: Nothing can be done now.

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha) Sir, you will please appreciate that Shri Yashpal Singh is a Member who never behaves in the manner that he is doing now. You should also try to understand that he is deeply hurt and he is grieved over some procedural mistake. At least the Chair should say that something wrong has happened instead of saying that it is all over. When there is a substantive motion, he has a right to reply and it is only proper for you to call upon him to reply.

Shri Koya: Sir, what is your ruling to my point of order? I want it to go on record.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order.

15.08 hrs.

STATEMENT *RE*: GROUNDING OF CARAVELLES BY THE INDIAN AIRLINES CORPORATION

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): Sir, I beg to lay on the Table a statement on the grounding of Caravelles by the Indian Airlines Corporation. [*Placed in Library. See* No. LT-4721/65]. If there are any questions, hon. Members may ask them tomorrow.

15.08¼ hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*. ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL —*Contd.*

श्री यशपाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे मौका न दे कर सरासर मेरे साथ बेइंसाफी की है।

Shri Swell: Sir, I rise to a point of order. I have been sitting here and listening to the speeches very attentively. When Shri Mirza finished his speech, several hon Members got up and wanted to speak. Immediately, without giving any hon. Member a chance to speak, you, Sir, called on the hon. Minister to reply. I was under the impression that more hon. Members would be given a chance to participate in the debate. I am sure, Shri Yashpal Singh was also under that impression.

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry, nothing can be done now.

श्री यशपाल सिंह: मैंने 20 दफे खड़े हो कर पूछा लेकिन आप ने मुझे मौका नहीं दिया तो मेरे साथ यह बेइंसाफी नहीं तो और क्या है? यह सब्जीमंडी नहीं है डिक्टेटरशिप नहीं है। यह कोई